



RNI No. MPIN/2018/76422

बेबाकी के साथ.. सच

माही की गुंज

www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

वर्ष-08, अंक - 44

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 20 अगस्त 2026

पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

खवासा क्षेत्र इतना उपेक्षित और जनप्रतिनिधि इतने असहाय क्यों...?

माही की गुंज, झाबुआ।

संजय भटवेरा

भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रतिनिधियों के अनुसार मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और अगर इसमें स्थानीय निकाय को जोड़ दे तो यहां ट्रिपल इंजन हो जाता है। क्योंकि यहां पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक में अधिकांश भाजपा समर्थित ही और ट्रिपल इंजन वाली गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ती है। लेकिन थांदला विधानसभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और विधानसभा में पार्टियों के गणित बनाने व बिगाड़ने वाला खवासा क्षेत्र आजादी के अमृत महोत्सव और ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद अभी तक उपेक्षित ही है। यहां भाजपा समर्थित जनपद उपाध्यक्ष अपनी पार्टी के खिलाफ जनता की वाजिब मांग पर सड़कों पर उतरी। लेकिन फिर भी नतीजा शून्य ही रहा। यही नहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी सार्वजनिक रूप से जनता की मांग को जायज ठहराते हैं लेकिन पदों के पीछे तो वे अपनी सरकार को दोषी ठहराते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से डरते हैं। खवासा क्षेत्र की वाजिब मांगों को लेकर ग्राम पंचायत खवासा के उपसरपंच मनोहर बारिया ने सोशल साइट पर अपना दर्द बर्खा करते हुए सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया है और उन्होंने तीखे शब्दों में लिखा है कि, खवासा क्षेत्र के साथ इतना भेदभाव क्यों...? क्या खवासा क्षेत्र किसी दूसरे ग्रह पर स्थित है...?



न झाबुआ जिले की सिमा में बन रहे इस माही डेम से नर्मदा नहर से खवासा को मिलेगा पानी !

यही नहीं पेयजल की समस्या और उसके निदान के लिए वर्षों पुरानी मांग माही या नर्मदा की नहर के लिए उन्होंने लिखा है, भाजपा लाए, कांग्रेस लाए, भारत आदिवासी पार्टी लाए, आम आदमी पार्टी लाए, जयस लाए या फिर किसी चोर को लाए जो खवासा में माही या नर्मदा की नहर ला सके।

31 जुलाई की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर

मोहन यादव का थांदला दौरा था। क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि, इस शासकीय कार्यक्रम में खवासा क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन मंच से मुख्यमंत्री द्वारा खवासा क्षेत्र का नाम तक न लेना क्षेत्रवासियों को निराश कर गया। जबकि तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान देर रात्रि में हुई सभा में

घोषणा की गई थी कि, नर्मदा का पानी खवासा में लाया जाएगा। वह घोषणा आज तक महज घोषणा ही बनी हुई है। वर्तमान में कुकड़ीपाड़ा ग्राम में एक बड़ा डेम बन रहा है। लेकिन विडंबना देखिए उसका पानी रतलाम जिले और धार जिले वासियों को मिलेगा लेकिन महज 18-20 किलोमीटर दूर स्थित खवासा या क्षेत्र को नहीं मिलेगा। यही नहीं मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी से जा रही नर्मदा नहर के लिए खवासावासियों ने एक प्रभावी आंदोलन भी किया था। मौके पर तो आश्वासन देकर अधिकारियों ने अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन बाद में पत्र जारी कर उस योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी खामियां बतलाकर कार्य न किया जाना बतला दिया। जिसके बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश है कि, जनता के साथ ही जनप्रतिनिधिओ की वाजिब मांगों को भी शासन-प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जनता, जनप्रतिनिधियों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। वहीं जनप्रतिनिधि अपने ही सरकार में खुद को असहाय और बेबस महसूस कर रहे हैं।

इसके अलावा क्षेत्र की लगभग 1 लाख आबादी होने के बावजूद उपस्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त चिकित्सक न होना, महिला चिकित्सक न होना, उपस्वास्थ्य केंद्र को उबयन करके स्वास्थ्य केंद्र बनाने, पुलिस चौकी को पुलिस थाना और महाविद्यालय खोलने की मांग भी शासन से की गई है। अब देखना ये है कि शासन इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है ...?

निर्दय मां मासूम को मरने के लिए छोड़ गई, पुलिस ने बचाई जान

माही की गुंज, रायपुरिया।

कुछ लोग अपने पाप छुपाने के लिए किसी मासूम को जान तक दाव पर लगा देते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंगलवार को रायपुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवली में देखने को मिला। जहां एक नवजात शिशु के खुले में पड़े होने की जानकारी ग्रामीणों को मिली। नवजात शिशु जीवित अवस्था में था जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना रायपुरिया पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए पेटलावद सिविल अस्पताल पहुंचाया।



घटना की जानकारी सामने आते ही क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि, आखिर इस नवजात शिशु को जन्म के बाद इस तरह मिट्टी में किसने छोड़ा? फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि, बच्चे को वहां क्यों छोड़कर गया था और इसके पीछे क्या वजह रही।

रायपुरिया थाना प्रभारी गीता जाटव ने चर्चा में बताया कि, नवजात फिलहाल स्वस्थ है। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

राम मंदिर चढ़ावे पर रेणुका चौधरी का सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी, वंदे मातरम् विवाद और राजनीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राम मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल द्वारा चंपत राय को आरोपों से मुक्त किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही अदेसा था कि बड़े लोगों को बचाने के लिए निचले स्तर पर काम करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।



रेणुका चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा और चंपत राय को बचा लिया जाएगा। उन्होंने मंदिरों के निर्माण और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी आस्था और मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पूर्व महासचिव चंपत राय

और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को आरोपों से मुक्त कर दिया है। मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद दोनों ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दिया था। इसके बाद विशेष जांच दल ने और संग्रह से जुड़े मामले में दोनों से पूछताछ की थी।

वंदे मातरम् के पूरे गीत को राजनीतिक और हिंदू-मुस्लिम विवाद से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि जिस समय यह निर्णय लिया गया था, उस समय परिस्थितियां अलग थीं। आज ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह वही लोग जानें। उन्होंने इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

राजनीति में नए दलों के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि न्यायालय की एक टिप्पणी के बाद कोई नया राजनीतिक दल अस्तित्व में आ जाएगा।

तारिक रहमान के सामने भारत की चुनौती

नई दिल्ली।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन अब तक उनकी नई दिल्ली यात्रा को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। भारत की ओर से उन्होंने नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन तारिक रहमान ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

तारिक रहमान इसी वर्ष फरवरी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद भारत ने उन्हें नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि, उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत के बजाय मलेशिया का रुख

किया। इसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा भी की। ऐसे में अब उनकी भारत यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है।



बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच कई सप्ताह से बातचीत चल रही है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ मौजूदा संबंधों के

माहौल को लेकर भी चिंता जताई है। मंत्रालय के प्रवक्ता ए.के.एम. शाहिदुल करीम ने कहा कि 5 अगस्त को दिल्ली के विदेश संवाददाता क्लब में अपदस्थ प्रधानमंत्री शोख हसीना की पत्रकार वार्ता से दोनों देशों के संबंधों का माहौल प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। इसके बाद दोनों देशों के बीच

संबंधों और संभावित यात्रा को लेकर बातचीत और महत्वपूर्ण हो गई है। जानकारों के अनुसार भारत के लिए बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद संवाद बनाए रखना जरूरी होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा, सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

मौजूदा परिस्थितियों में तारिक रहमान सरकार के साथ संवाद कायम रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राउज एवेन्यू



न्यायालय में पेश किया। उन्हें 11 मई 2024 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।

जैन की गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज शोधन संयंत्र के उन्नयन और निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में हुई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि परियोजना और निविदा प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया।

जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जैन को गिरफ्तार करने के लिए जांच एजेंसी पर दबाव बनाया गया था। उन्होंने गृह मंत्री से गिरफ्तारी के पीछे का कारण स्पष्ट करने की मांग की।

केजरीवाल ने दावा किया कि जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने उन्हें बताया था कि बुधवार सुबह तक जैन को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं थी। उनके अनुसार, दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित फोन के बाद गिरफ्तारी का निर्णय लिया गया और अधिकारी को जैन को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अब गिरफ्तारियां अपराध के आधार पर नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा के आधार पर की जा रही हैं। हालांकि, ये आरोप केजरीवाल के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

महंगा हुआ कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों पर बढ़ा दबाव

नई दिल्ली।

भारतीय तेल रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की खरीद लगातार चुनौती बनती जा रही है। वैश्विक बाजार में ब्रेट कच्चे तेल की कीमतें पिछले दो सप्ताह में करीब 10 डॉलर बढ़कर 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की उपलब्धता घटने से खाड़ी और पश्चिम अफ्रीका से मिलने वाले तेल पर भी भारी अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ रही है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारतीय रिफाइनरियों को रूसी और वेनेजुएला के कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट लगभग खत्म हो गई है। इससे कंपनियों की कच्चे तेल की खरीद लागत बढ़ने की आशंका है। इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और तेल कंपनियों के लाभ पर पड़ सकता है। अनुमान के अनुसार कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल 10 डॉलर की बढ़ोतरी से कंपनियों पर करीब 6 रुपए प्रति लीटर तक का आंतरिक भार पड़ सकता है।

खाड़ी देशों

से कच्चा तेल खरीदना भी महंगा हो गया है। आपूर्ति में कमी का फायदा तेल कारोबारी उठा रहे हैं। भारतीय रिफाइनरियों को खाड़ी देशों से तेल खरीदने के लिए तत्काल बाजार का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां कारोबारी दुबई-ओमान मूल्य सूचकांक पर 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल का अतिरिक्त प्रीमियम मांग रहे हैं। दुबई-ओमान मूल्य सूचकांक खुद ब्रेट



से करीब 6 से 7 डॉलर प्रति बैरल महंगा है। इसके बाद भारतीय रिफाइनरियों के लिए खाड़ी का कच्चा तेल ब्रेट की तुलना में

मार्ग और जहाज से जहाज में तेल स्थानांतरण जैसी व्यवस्थाओं के लिए कारोबारी अतिरिक्त शुल्क मांग रहे हैं। इससे

तेल की कुलई लागत भी बढ़ रही है।

खाड़ी देशों के बाद पश्चिम अफ्रीका से मिलने वाला कच्चा तेल भी भारतीय रिफाइनरियों के लिए महंगा हो गया है। ऐसे में कंपनियां अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे दूर के देशों से वैकल्पिक स्रोत तलाश रही हैं।

कुछ समय पहले तक रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए आकर्षक विकल्प था, क्योंकि उस पर अच्छी छूट मिल रही थी। अब यह छूट लगभग खत्म हो चुकी है। इसी तरह

वेनेजुएला के तेल पर मिलने वाली छूट भी काफी कम हो गई है। इससे भारतीय रिफाइनरियों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है।

यदि खाड़ी क्षेत्र में कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य नहीं होती और रूसी तेल पर मिलने वाली छूट वापस नहीं आती है, तो भारत की कच्चे तेल की खरीद लागत और बढ़ सकती है।

हत्या का मुख्य आरोपी देवा और उसका साथी धराए

अवैध संबंधों के शक में हरिराम सीरवी की हत्या, समाजजनों ने किया पुलिस का स्वागत

माही की गूंज, पेटलावद।

2 अगस्त की रात हुई वारदात के 15 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित देवा उर्फ देवीलाल समेत दो फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को झाबुआ एसपी देवेन्द्र पाटीदार पेटलावद पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों का पैदल जुलूस निकालकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले के सामने आने के बाद से सिरवी समाज सहित आम जनता में अपराधियों को पकड़े जाने में हो रही देरी को लेकर रोष था ।

अटल बस्ती में हुई थी वारदात

पुलिस के अनुसार 1-2 अगस्त 2026 की रात फरियादिया भुलीबाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी अटल बस्ती पेटलावद ने थाना पेटलावद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके परिचित हरिराम पिता गोमाजी गेहलोत, निवासी धुलैट, जिला धार के साथ देवा सिंगाड़, एक विधि-विरुद्ध बालक, देवा के जमाई एवं अन्य लोगों द्वारा गाली-गलौज और मारपीट की गई थी।गंभीर चोट लगने के बाद हरिराम को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान

उसकी मौत हो गई। मामले में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 349४2026 के तहत बीएनएस की धारा 103(1), 1 1 5 (2) , 2 9 6 (2) , 351(2), 3(5) में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान बनाए गए मारपीट के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश भी की गई थी।

अवैध संबंध बने हत्या का कारण

एसपी देवेन्द्र पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, पुलिस पृष्ठताछ में मुख्य आरोपित देवा उर्फ देवीलाल ने भुलीबाई के साथ पिछले करीब 12 से 13 वर्षों से संबंध होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार देवा ने भुलीबाई को अटल बस्ती में मकान लेकर पत्नी के रूप में रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मृतक हरिराम की भुलीबाई से दोस्ती थी। जब देवा को हरिराम



मुखबिर तंत्र और तकनीकी जांच के आधार पर लगातार आरोपितों की तलाश की।

पूर्व से संगीन अपराधों में लिप्त था आरोपी देवा, भाजपा नेता होने के चलते

बचता रहा

गिरफ्तार मुख्य आरोपित देवा उर्फ देवीलाल पिता कच्छू सिंगाड़, उम्र 46 वर्ष, निवासी महापुरा, हाल संजय कॉलोनी राजगढ़, जिला धार को पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। पुलिस के अनुसार देवा के खिलाफ राजगढ़ सहित अन्य थाना क्षेत्रों में शासकीय कार्य में बाधा, अवैध वसूली, दुष्कर्म, जमीन पर कब्जा सहित करीब 13 गंभीर आपराधिक मामले पहले से पंजीबद्ध हैं।

दूसरा गिरफ्तार आरोपित नरसिंह पिता

अम्बाराम कोडीवाल कुमावत, उम्र 42 वर्ष, निवासी सोनगढ़, थाना राजगढ़, जिला धार है। मुख्य आरोपी देवा भाजपा से जुड़ा है और वर्तमान में देवा की पत्नी भी सरदारपुर जनपद अध्यक्ष भाजपा से जुड़ी है,देवा के कई बड़े भाजपा नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर है, बताया का रहा है देवा भाजपा से विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुर विधानसभा से टिकिट के सपने भी रखता था।

दो आरोपी पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं जेल, मुख्य आरोपी का निकाला जुलूस

इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही अर्जुन उर्फ राजू भूरिया निवासी छोटा माछलिया तथा एक विधि-विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया था और उन्हें जिला जेल झाबुआ भेजा जा चुका है। इस तरह मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई में कुल चार आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है, सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार मुख्य आरोपित देवा उर्फ देवीलाल और नरसिंह को पैदल जुलूस के रूप में न्यायालय ले जाकर पेश किया।

उत्साह पूर्वक मनाया स्वतंत्रता दिवस

माही की गूंज, काकनवानी।

बारिश की रिमझिम मौसम में बड़ा ही उत्साह पूर्वक मिडिल स्कूल प्राथमिक शाला एवं हाई स्कूल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर स्थानीय स्कूल से बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए बस स्टैंड तक कतार बंद पैली निकाली। सभी बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए राष्ट्रभक्ति गीत के साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे। तो वही स्कूल की छात्राओं द्वारा हाई सैकेंडरी स्कूल पर स्वागत भाषण के साथ राष्ट्रीय गीत एवं देशभक्ति के नाम संदेश देते हुए अपने प्रतिभा को दिखाया। इसी दौर में छोटी-छोटी बच्चियों ने भी देशभक्ति गीत पर डांस किया एवं नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल के समस्त स्टाफ प्रिंसिपल बहादुर चरपोटा ,पुलिस स्टाफ सहित काफी लोग उपस्थित थे।

पंचायत पर फहराया तिरंगा

स्थानीय ग्राम पंचायत पर सरपंच श्रीमती सांता देवी ने और उपसरपंच, पंचों एवं गांव के वरिष्ठ नागरिकों व स्कूल के बच्चों एवं पंचायत कर्मी की उपस्थिति में तिरंगा फहराया इसके पश्चात पंचायत में ग्राम सभा की गई इसी दौरान थाना काकनवानी पर थाना प्रभारी द्वारा तिरंगा लहराया गया।



जिला अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत

माही की गूंज ,करवड़ ।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश परमार के करवड़ प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता एवं युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। नगर में उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान जिला अध्यक्ष का विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर एवं पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

सरहद पर जवानों की कलाई पर सजेगी बहनों की राखी

माही की गूंज, थांदला।

रक्षा सूत्र समिति थांदला के तत्वाधान में पिछले 23 वर्षों से सरहदों पर तैनात फौजी भाईयो के लिये समस्त शैक्षणिक संस्था एवं नगर की बहनों द्वारा राखियां एकत्र कर भेजे जाने का क्रम इस वर्ष भी स्थानीय नगर परिषद बैडमिंटन हाल में सम्पन्न हुआ इस वर्ष इस आयोजन के प्रायोजक लायंस क्लब द्वारा किया गया। आयोजन में तहसीलदार सुकदेव डावर मुख्य आतिथ्य के साथ लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि, पीएम श्री विद्यालय प्राचार्य आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्व प्रथम रक्षासूत्र समिति अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने 23 वर्षीय रक्षा सूत्र के आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। वही लायंस क्लब थांदला अध्यक्ष ओमप्रकाश बजाज ने इस आयोजन को ले कर चरणबद्ध तरीके से कैसे सम्पन्न किया

गया एवं आने वाले वर्षों में वृहद स्तर पर जिला स्तर पर इस आयोजन करने की मंशा जाहिर की।

जवानों के त्याग को किया नमन

मुख्य अतिथि तहसीलदार सुकदेव डावर ने अपने उद्बोधन में कहा कि, भारतीय सैनिक बर्फीली सीमाओं से लेकर तपते रेगिस्तान तक विषम परिस्थितियों में दिन-रात देश की रक्षा में डटे रहते हैं। जवानों के इसी साहस और त्याग के कारण देशवासी सुरक्षित जीवन जीते हैं। छात्राओं की ओर से भेजी गई राखियां केवल रक्षासूत्र नहीं, बल्कि सरहद पर तैनात जवानों के प्रति देश की बेटियों का स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता हैं। इन राखियों के जरिए सैनिकों को यह संदेश भी दिया गया है कि, वे भले ही अपने परिवार से दूर हों, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

नगर में पिछले पांच दिनों से नहीं हो रहा जल सप्लाई

माही की गूंज, थांदला।
मुकेश भट्ट

डबल इंजन की भाजपा सरकार में नगर परिषद में अंधेर नगरी चौपट राजा सा राज चल रह है। इसको ले कर परिषद में कई मर्तबा बहस बाजी भी होती आई है तो वार्ड क्रमांक 9 के जुझारू पार्षद अचानक जलकर एवं संपत्ति कर बढ़ाने का विरोध अपनी ही परिषद से लेकर कलेक्टर और मंत्री स्तर तक कर चुके है। शिकायत के बावजूद उसके नगर में गंदगी,ड्रेनेज,अतिक्रमण सहित पेयजल की समस्याएँ मुंह फाड़ती नजरवा रही है। बारिश होने के बावजूद भी नगर में भीषण गर्मी की तरह पेयजल समस्या से आम

नागरिक परेशान हो रहे है। बड़ी बात तो यह कि आरो का पानी देने का दावा करने वाली नगरपरिषद के नगर में अधिकांश जनता बाजार से आरो का पानी केन खरीद कर प्यास बुझा रहे है। नगर में पिछले 5 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने से नागरिकों में आक्रोश है।

जवाबदार रिसीव नहीं करते काल

बताते है कि, नगर परिषद में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। न तो परिषद में आपसी सामंजस्य है और न ही परिषद के अधिकारी, कर्मचारियों में कार्य को ले कर पटरी बैठ रही है। फलतः नगर की जनता अपने कार्यों, समस्याओं को लेकर परेशान नजर

आते है। बीते समय वाटर वर्क्स पर गैस रिसाव और आगजनी की घटना का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर घटना किन कारणों से हुई। इधर पेयजल वितरण को लेकर पदस्थ इंजीनियर ने ठेका पद्धति खत्म होने के बाद से पेयजल सप्लाई नए ओर अनुभवहीन हाथों में दे रखी। जिसके चलते नगर में बार-बार पेयजल वितरण गड़बड़ाने लगता है। इस संबंध में जवाबदार इंजीनियर से ले कर अधिकारी से चर्चा करना चाहे तो काल रिसीव नहीं करते।

मेटेनेंस का अभाव

माही की गूंज ने जब नगर में बीते 5 दिनों से नहीं हो रहे जल वितरण को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि, नगर परिषद में पेयजल सप्लाई करने

हेतु लगभग आधा दर्जन पानी की टंकिया है किंतु इन टंकियों को भरने हेतु एक मात्र विद्युत मोटर है। जिसके जलने के चलते नगर में पेयजल समस्या बनी हुई है। बताते है कि, नगर परिषद के वाटरवर्क्स में पूर्व नगर की पानी टंकिया भरने हेतु एकाधिक विद्युत पंप थे किंतु समय के साथ वे सभी पंप भी वाटरवर्क्स से नदारद हो गई। अब यह विद्युत पंप कहा ओर कैसे गई यह तो वाटरवर्क्स के जिम्मेदार ही जाने। नए ओर अनुभव हीन पेयजल सप्लायर वितरण व्यवस्था को सुचारु रखने में असमर्थ है। जबकि पूर्व के वितरक अनुभवी होने के साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या आने पर स्वयं अपने अनुभव से मेटेनेंस कर पेयजल वितरण व्यवस्था समथ



पर कर लेते थे। अब भी नगरपरिषद पेयजल व्यवस्था नहीं सुधरती तो नागरिक मजबूरन आंदोलित होने को विवश होंगे जिसकी जवाबदारी भी नगर परिषद की होगी।

डेढ़ किलोमीटर क प्रभात फैरी के साथ मना स्वतंत्रता दिवस



माही की गूंज, खवासा।
सुनिल सोलंकी

80 वाँ स्वतंत्रता दिवस 10 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा के साथ धूमधाम से मना। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह स्थल कन्या शाला परिसर से ग्राम में करीब डेढ़ किलोमीटर से अधिक लंबी बच्चों की प्रभात फेरी निकली। प्रभातफेरी में स्काउट गाइड आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बच्चों के हाथ में तिरंगा लेकर छोटे-छोटे बच्चे राष्ट्रीय नारों के साथ उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रभात फेरी ग्राम के मुख्य मार्ग से होते हुए जब ग्राम पंचायत परिसर पहुंची तो प्रभात फेरी का बच्चों का पिछला सीरा बजरंगबली मंदिर से आगे जैन मंदिर तक था। इतनी लंबी प्रभात फेरी को देखकर हर किसी ने खुशी जाहिर की।

प्रभात फेरी ग्राम पंचायत परिसर पहुंचने के बाद यहां सरपंच श्रीमती गंगाबाई खराड़ी ने

प्रतिभावान का सम्मान, तिरंगा यात्रा में दिखी अनियमितताएं

ध्वजारोहण किया और तत्पश्चात जन गण मन का गान हुआ। इसके पश्चात कन्या शाला परिसर में हुए मुख्य समारोह में सभी शासकीय व अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने एक से एक वि श र े ष

गया। उक्त सम्मान में चारों छात्राओं ने बाजी मारी जिसमें 11 हाई स्कूल में संत तेरेसा स्कूल की छात्रा याशिका पिता कृष्ण कुमार पाटीदार ने 500 में से 478 अंक के साथ 95.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। याशिका ने क्षेत्र के साथ जिले की टॉप-10 सूची में भी स्थान प्राप्त

द्वारा सम्मानित किया गया।

वहीं हाई सैकेंडरी स्कूल में सत्य साईं कान्वेंट स्कूल की छात्राओं ने बाजी मारी जिसमें क्षेत्र की 5 हाई सैकेंडरी में छात्रा चिंची पिता दिनेश पाटीदार ने गणित संकाय में 500 में से 445 अंक के साथ 89 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम एवं गणित संकाय में ही छात्रा दिव्या पिता मयंक पाटीदार ने 500 में

आह्वान पर आजादी पर्व पर वंदे मातरम के 150 वे वर्षगांठ पर 10 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत जिले में भी गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में 13 अ ग स् त



को खवासा में भी ग्राम पंचायत परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली। जिसमें स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ गणमान्य लोगों एवं जननेताओं ने हिस्सा लिया।

उक्त तिरंगा यात्रा ग्राम पंचायत परिसर से निकली और बस स्टैंड होते हुए बजरंगबली मंदिर, नीम चौक से राम मंदिर होते हुए पुरानी टंकी से सीधे जैन मंदिर होते हुए

ग्राम पंचायत परिसर पहुंची।

उक्त यात्रा पूर्व नियोजित होने के बावजूद ग्राम

से 441 अंक के साथ 88.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया जिनका भी मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मान पत्र के साथ परितोषित चेक देकर सम्मान किया।

समारोह के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत थांदला की उपाध्यक्ष श्रीमती माया प्रेमसिंह चौधरी, आयोजन की अध्यक्षता कर रही सरपंच श्रीमती गंगाबाई खराड़ी, विशेष अतिथि डॉक्टर श्री चूंडवत, नंदलाल मेड, पूर्व सरपंच रमेश बारिया, आदि जनप्रतिनिधि, गणमान्य व पंचगण उपस्थित थे।

तिरंगा यात्रा में दिखी अनियमिताएं



बच्चों ने मुख्य समारोह पर दी शानदार प्रस्तुतियां ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

13 अगस्त को निकली तिरंगा यात्रा में फोटो जुबानी अनियमिता जो बनी आम चर्चा का विषय ।

जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए, तो समाज को ढहरकर सोचना होगा

माही की गूंज, झाबुआ। धर्मेन्द्र पंचाल

लालच, दिखावे, डिजिटल अफवाहों और कमजोर होते पारिवारिक संवाद के बीच समाज को खुद से पृष्ठना होगा की हम अपने बच्चों को आखिर क्या सिखा रहे हैं...? कुछ अपराध सिर्फ अपराध नहीं होते वे समाज के चेहरे पर पड़े ऐसे सवाल होते हैं, जिनसे आंखें चुराए आसान नहीं होता। हाल में सामने आई इंदौर, केरल और भोपाल से जुड़ी घटनाओं ने इसी तरह का गंभीर सवाल खड़ा किया है। इंदौर में पत्नी की हत्या और बच्चों को तालाब में फेंकने की घटना ने पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती हिंसा की भयावह तस्वीर सामने रखी। केरल में बाइक और महंगे मोबाइल जैसी वस्तुओं की चाहत से जुड़े दादा की हत्या के मामले ने रिश्तों पर उपभोक्तावादी लालच के असर को सामने रखा। वहीं भोपाल में मानव अंग बेचकर करोड़ों रूपए कमाने जैसी अफवाह और लालच से जुड़ी कथित साजिश में एक किशोर की जान चली गई।

इन मामलों में वास्तविक कारणों, आरोपों और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा। लेकिन इन घटनाओं ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल जरूर रख दिया है कि, क्या हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं...?

जब वस्तुएं रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएं

मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए, इन इच्छाओं में अपने आप में कुछ गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है, जब किसी वस्तु को हासिल करना रिश्तों, नैतिकता और इंसान की जिंदगी से भी

बड़ा हो जाए।

सोशल मीडिया ने तुलना की इस प्रवृत्ति को और तेज किया है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चमकदार जिंदगी हमें बार-बार यह महसूस कराती है कि जो हमारे पास है, वह कम है और जो दूसरे के पास है, उसे हासिल करना जरूरी है।

यहीं परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों और युवाओं को यह समझाना होगा कि, जरूरत और लालच के बीच एक सीमा होती है और उस सीमा का नाम विवेक है।

परिवार साथ है, लेकिन संवाद

कहां है...?

भारतीय परिवार की सबसे बड़ी ताकत हमेशा संवाद, संवेदना और आपसी सहयोग रही है। लेकिन आज कई परिवारों में एक अजीब स्थिति दिखाई देती है कि लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, फिर भी एक-दूसरे के मन से दूर होते जा रहे हैं।

माता-पिता बच्चों की पढ़ाई, करियर और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बच्चे अपनी अलग दुनिया में व्यस्त हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने संवाद के कई पुराने रास्तों की जगह ले ली है।

ऐसे में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि, बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। यह जानना भी जरूरी है कि, वह क्या देख रहा है, किससे प्रभावित हो रहा है और इंटरनेट पर किस तरह की



जानकारी ग्रहण कर रहा है।

बच्चों पर केवल निगरानी रखने से ज्यादा जरूरी है, उनके साथ विश्वास का रिश्ता बनाना। ऐसा रिश्ता जिसमें बच्चा अपनी परेशानी, गलती, डर या किसी गलत जानकारी के बारे में बिना भय के बात कर सके।

हर वायरल वीडियो सच नहीं होता

भोपाल से जुड़ी घटना डिजिटल युग के एक और खतरनाक पहलू की ओर ध्यान खींचती है। फर्जी और भ्रामक जानकारी। आज किसी भी दावे को वायरल होने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसे सच साबित करने के लिए प्रमाण, वैज्ञानिक जांच और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। यही

कारण है कि, स्कूलों और परिवारों में डिजिटल साक्षरता को केवल मोबाइल चलाना सीखने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि, किसी वीडियो, रील, पोस्ट या संदेश को देखकर तुरंत विश्वास न करें और न ही उसे आगे बढ़ाएं।

इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी

बहुत है, लेकिन हर जानकारी

ज्ञान नहीं होती

अपराध रोकने की शुरुआत घर से हो सकती है हर घटना के बाद पुलिस और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, सवाल उठना भी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ

कठोर, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है।

लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि, अपराध होने के बाद कानून काम करता है, अपराध होने से पहले समाज को काम करना होता है।

घर में बच्चों से बातचीत, स्कूल में मूल्य शिक्षा, डिजिटल दुनिया की समझ, मानसिक तनाव को गंभीरता से लेना और गलत संगत या खतरनाक विचारों के संकेतों को समय रहते पहचानना ये सब अपराध की रोकथाम का हिस्सा हैं।

हमें बच्चों को केवल प्रतियोगिता में जीतना नहीं सिखाना है। उन्हें हार स्वीकार करना, गुस्से पर नियंत्रण रखना, लालच से बचना, किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके विश्वास

न करना और सबसे बढ़कर दूसरे इंसान के जीवन का सम्मान करना भी सिखाना होगा।

बदलाव की शुरुआत हमसे होगी

समाज को बदलने की जिम्मेदारी केवल सरकार, पुलिस या स्कूल की नहीं है। इसकी शुरुआत परिवार से होती है और परिवार से निकलकर समाज तक पहुंचती है।

हमें तय करना होगा कि, आने वाली पीढ़ी को हम केवल सफल देखना चाहते हैं या संवेदनशील भी।

डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कारोबारी या किसी बड़े पद तक पहुंचना जीवन की उपलब्धि हो सकता है, लेकिन एक अच्छे इंसान बने रहना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि है।

इंदौर, केरल और भोपाल जैसी घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए पर्याप्त हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि तकनीक आगे बढ़ सकती है, जीवनशैली बदल सकती है और इच्छाएं बढ़ सकती हैं लेकिन इंसानियत पीछे नहीं छूटनी चाहिए।

आज समाज को फिर से कुछ बुनियादी बातें अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाने की जरूरत है। रिश्ते किसी वस्तु से बड़े हैं...। इंसान की जिंदगी किसी कीमत से बड़ी है...। सच किसी वायरल वीडियो से बड़ा है... और संवेदना किसी भी सफलता से बड़ी है...।

अगर हम यह समझ जाएं, तो शायद अपराध की अगली खबर आने का इंतजार करने के बजाय हम उस मानसिकता को बदलना शुरू कर सकेंगे, जिससे अपराध जन्म लेते हैं। क्योंकि समाज केवल कानून से सुरक्षित नहीं होता। समाज तब सुरक्षित होता है, जब उसके लोगों के भीतर इंसानियत जिंदा रहती है।

गायत्री उपवन में पौधों के रोपण की नींव रखी

माही की गूंज,पेटलावद।

अखिल विश्व गायत्री परिवार, पेटलावद द्वारा अखण्ड ज्योति शताब्दी वर्ष एवं परम वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से «वृक्ष गंगा अभियान» का शुभारंभ किया गया है। अभियान के अंतर्गत गोविन्दपाड़ा फॉरेस्ट रेंज में 2400 पौधों के रोपण की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसे «गायत्री उपवन» के रूप में विकसित किया जाएगा।अभियान के शुभारंभ अवसर पर पेटलावद तहसील के वरिष्ठ एवं परम साधक गायत्री परिजन मोतीलाल गामड़ द्वारा विधि-विधानपूर्वक भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी रेंजर - प्रेमसिंह चारेल गायत्री परिवार के परिजन एवं वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।



स्वतंत्रता दिवस पर नई पंचायत भवन का शुभारंभ

माही की गुंज,बनी।ऋषभ गुप्ता

80वे स्वतंत्रता दिवस पर नई पंचायत भवन का शुभारंभ किया गया। 80 वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरपंच श्रीमती नानुड़ी बाई के द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम बनी में निर्मित नई पंचायत भवन का पंडित जितेंद्र शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ करवाया गया। तत्पश्चात जनपद सदस्य शंभूलाल निनामा द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी कालू सिंह मचार, सचिव देवीलाल भाबर, सहायक सचिव भारत सिंह चौहान, मौबिलाइज भरत गणावा, समस्त पंच एवं गणमान्य नागरिको ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

स्वतंत्रता दिवस एवं नई पंचायत भवन के उपलक्ष में पधारे सभी जनों को शल्पाहार कराया गया। प्रभात फेरी गांव के मुख्य मार्ग से नहीं गुजर पाई सुबह से पानी गिरने की वजह से सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों के हित में यह निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर बच्चों के द्वारा अपने-अपने विद्यालयों के प्रांगण में आयोजन किये । तत्पश्चात बच्चों को मिठाई का वितरण किया गया। नई पंचायत भवन के उद्घाटन के बाद 18 अगस्त को नई पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया जिसमें ग्रामीणों ने

अच्छी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवरकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए पंचायत भवन के सामने पुराने जर्जर भवन से नई पंचायत भवन की छवि धूमिल होने की चर्चाएं चलती रही एवं पंचायत भवन के सामने मुख्य मार्ग होने से पंचायत भवन स्पष्ट नहीं दिखाई देने की बात भी लोगों की जुबा पर चलती रही। वैसे भी स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पंचायत के सामने स्थित पुराने खंडहर भवन को नष्ट कर गंदगी को हटवाना चाहिए तभी स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नई पंचायत भवन के पास एक तरफ उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी दूसरी तरफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो स्वच्छता के प्रतीक है। इन सभी की ओर ध्यान

आकर्षित करते हुए सरपंच महोदया को पंचायत भवन के आग्ने-सामने फैली गंदगी और जर्जर



नई पंचायत भवन का हुआ शुभारंभ ।



पंचायत भवन के सामने स्थित खंडहर भवन ।

भवन को अति शीघ्र हटाना चाहिए जिससे पंचायत भवन की खूबसूरती में चार चांद लग जाए।

8 दिन में 3 बार चोरी: बामनिया की पानी सप्लाई पर संकट, ग्राम पंचायत के फिल्टर प्लांट को निशाना बना रहे चोर

माही की गूंज, बामनिया।

ग्राम पंचायत बामनिया में चोरों ने हद कर दी है। महज 8 दिनों के भीतर पंचायत के पानी सप्लाई फिल्टर प्लांट को तीन बार निशाना बनाया जा चुका है। लगातार हो रही चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं से पूरे ग्राम की जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। अब लोगों को पीने के पानी के लिए भी परेशान होना पड़ सकता है।

तीन बार बना निशाना, उपकरण

क्षतिग्रस्त

मिली जानकारी के अनुसार लाड़की बैराज के पास स्थित ग्राम पंचायत का पानी सप्लाई प्लांट चोरों के निशाने पर है। पहली और दूसरी घटना में चोर फिल्टर प्लांट से बिजली के केबल काटकर ले गए, केबल चोरी होने से मोटर और पंप संचालन ठप हो गया।

तीसरी घटना कुछ दिन बाद हुई। इस बार चोर पानी सप्लाई के मुख्य पाईप को उखाड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शायद वजन अधिक होने या किसी के आ जाने के डर से वे पाईप ले जाने में सफल नहीं हुए। गुस्से में आकर चोरों ने पाईप को बीच से तोड़कर वहीं छोड़ दिया।

इस तोड़ फोड़ से पाइप लाईन में रिसाव और लीकज की समस्या पैदा हो गई है। पानी सप्लाई से जुड़े इन महत्वपूर्ण उपकरणों को बार-बार नुकसान पहुंचने के कारण पूरी जलापूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर बामनिया गांव के हजारों निवासियों पर पड़ रहा है। कई वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित है और जो सप्लाई हो भी रही है उसमें प्रेशर बेहद कम है।

पुलिस को दी शिकायत, सुरक्षा पर सवाल

ग्राम पंचायत प्रशासन ने तीनों घटनाओं की सूचना लिखित रूप में स्थानीय पुलिस चौकी में दी है। पंचायत का कहना है कि, फिल्टर प्लांट एकांत जगह पर स्थित है और वहां न तो कोई सुरक्षा गार्ड है और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर रात में आसानी से घटना को अंजाम दे रहे हैं।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां एक चौकीदार रखने का सुझाव दिया है। लेकिन पंचायत का तर्क है कि, लाड़की बैराज क्षेत्र बिल्कुल सुनसान है। वहां न रहने की कोई व्यवस्था है, न रोशनी और न ही आपातकालीन मदद की सुविधा। ऐसे में अकेले एक व्यक्ति की

चौकीदारी करना भी जोखिम भरा है। पंचायत की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ लिखित आवेदन भी सौंपा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि, शिकायत की प्राप्ति रसीद अभी तक नहीं दी गई है, जिससे पंचायत के सामने आगे की कार्रवाई को लेकर भी असमंजस्य है।

नगरवासियों में आक्रोश,

जल्द कार्रवाई की मांग

लगातार चोरी से परेशान बामनिया के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि, गर्मी के मौसम में पहले ही पानी की किल्लत रहती है। अब चोरी की वजह से सप्लाई बंद हुई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि, फिल्टर प्लांट पर तुरंत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।

पंचायत सचिव ने बताया कि, क्षतिग्रस्त केबल और पाइप को बदलने में पंचायत पर आर्थिक



चोरों ने फोड़ पाईप ।

आर्थिक भार पड़ा है। बार-बार मरम्मत के बाद भी चोरी होने से बजट पर असर पड़ रहा है।

अब देखना होगा कि, पुलिस इस मामले में

कितनी जल्दी कार्रवाई करती है।

वरना 8 दिन में 3 चोरी की यह घटना कहीं पूरे गांव



फाड़ल फोटो: ये केबल चोरी कर ले गए चोर ।

को पानी के संकट में न धकेल दे।

संपादकीय

एक खत्म, दूसरा शुरू



झारखंड में करीब 25 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विवादित कंपनी टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी-14, जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही घोषणा कर दी कि जेपीएससी 11 व 13 की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं के घोषित परिणाम भी रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। यानी टीडीपीएल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी चुने गए, उनका चयन भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ग्यारह मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श किया। छात्र आंदोलन के दबाव में काम कर रही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली। दरअसल, छात्रों के कई खेमे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया, उनमें चौदहवीं जेपीएससी सिविल सेवा रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और सिविल जूनियर आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। दरअसल, इन परीक्षाओं का संचालन जेपीएससी के माध्यम से किया गया। वहीं दूसरी ओर सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरियां भी अब समाप्त मानी जाएंगी। सरकार ने वायदा किया है कि वर्ष 2014 के बाद हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच भी की जाएगी। यह जांच कार्य एक न्यायिक आयोग करेगा। बाकायदा एक आईएस अधिकारी की अध्यक्षता में सुधारों के लिये एक कमेटी भी बनायी गई है। हालांकि, कुछ आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि, सरकार की घोषणा के बाद छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन इस घोषणा के बाद सचिवालय परिसर में उन नियुक्त प्रतिभागियों की भीड़ जुट गई, जो जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करके नौकरी हासिल कर चुके थे। सरकार की घोषणा के तुरंत बाद विभिन्न चयनित प्रतिभागियों का हुजूम सचिवालय में जमा होना शुरू हुआ। उनके लिये यह खबर स्तब्ध करने वाली थी। उनका दुख और गुस्सा स्वाभाविक ही है।

बहरहाल, अब राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद हटाये गए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री एक बयान देकर दो हजार लोगों को सरकारी नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? वे इसे सरकारी अन्याय बता रहे हैं। उनकी दलील है कि हम सुबह नौकरी पर थे, लेकिन शाम होते ही हमें नौकरी से हटा दिया गया। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमें नौकरी मिली है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा सितंबर 2024 में फिर से हुई। फिर पेपर लीक की आशंका के बीच मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। साथ ही तीस दिसंबर को सफल प्रत्याशियों को बाकायदा नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब सरकार द्वारा ये नियुक्तियां रद्द करने से प्रतिभागी बदहवास हैं क्योंकि कई लोगों ने लोन लेकर अपना जीवन स्तर सुधारा, उनकी बैंक की किश्तें जा रही हैं। अब उनकी आंखों के सामने अंधेरा है। उनकी मांग है कि सरकार कायदे से जांच कर ले, लेकिन उन्हें नौकरी से न हटाए। सभी लोग धांधली से भर्ती नहीं हुए हैं। उनका तर्क है कि भीड़ के दबाव में निर्दोष लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। हटाये गए कर्मचारियों की आंखें नम हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दूसरी नौकरियां छोड़कर सरकारी नौकरी के प्रलोभन में आए। दुखी व हताश हटाये गए कर्मचारी बारिश में धरने पर बैठे रहे क्योंकि उन्हें अधिकारियों ने सचिवालय से बाहर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हटाए गए कर्मियों के घर वाले भी सदमे में हैं। राज्य सरकार भी मुश्किल में है क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों की दलील है कि उनका आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं सरकार के सामने हटाये गए अधिकारियों व कर्मचारियों का नया मोर्चा खुल गया है। हटाये गए कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वे सरकार के लिखित आदेश की प्रतीक्षा में हैं।

लोकतंत्र को संबल देता है अहिंसक प्रतिरोध

जानवर सोचते हैं या नहीं, पता नहीं, पर मनुष्य की एक पहचान यह मानी जाती है कि यह सोचता है। फ्रांसीसी विचारक डेकार्त ने कहा था, 'मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूँ।' यह जरूरी नहीं कि फ्रांसीसी विचारक की इस बात से हम सहमत हों ही, पर यह जरूरी है कि इस सोचने का अर्थ और महत्व समझा जाए। आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से किए गए प्रधानमंत्री के उद्‌बोधन में 'दिमागी नक्सलियों' के उल्लेख के बाद देश में एक विवाद-सा चल गया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि देश 'हथियारी नक्सलियों' से तो मुक्त हो चुका है, पर दिमागी नक्सलियों से मुक्त होना अभी बाकी है।

हालांकि उन्होंने यह तो नहीं बताया कि दिमागी नक्सली वे किसे कह रहे हैं, पर यह अवश्य कहा कि इन दिमागी नक्सलियों को चुन-चुनकर समाप्त करना होगा। वैसे, इस तरह के विशेषण प्रधानमंत्री जी पहले भी देते रहे हैं। कभी उन्होंने 'अर्बन नक्सली' कहकर एक विशेष सोच वाले लोगों को देश का दुश्मन कहा था, कभी 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' और कभी 'अराजकतावादी' कहकर।

नक्सलवाद की बात देश की राजनीति में साठ के दशक में सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव है नक्सलबाड़ी। वर्ष 1967 में वहां स्थानीय किसानों और भूस्वामियों के बीच भूमि-अधिकारों को लेकर एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास करने वाले चार मजूमदार और कानू सान्याल कर रहे थे। ये दोनों नेता यह मानते थे कि 'न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है।' एक असें तक यह सोच बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि में पनपती रही, पर गांधी के भारत को यह स्वीकार नहीं था। यह देश पीड़ितों के दमन को तो समाप्त करना चाहता है, पर हथियारों के बल पर नहीं। प्रधानमंत्री जिन हथियारी नक्सलियों के खात्मे की बात कर रहे हैं, वह यही नक्सली थे। सशस्त्र क्रांति में विश्वास करने वाले लोगों को नक्सलबाड़ी गांव के नाम से नक्सली कहा गया। देश के गृहमंत्री का दावा है कि लगभग आधी सदी के संघर्ष के बाद आज देश में ये हथियारी नक्सली लगभग समाप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक सीमा तक इस सफलता

का श्रेय ले सकती है, पर दलितों, आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध सोच को समाप्त करना न तो संभव है, न ही उचित। शोषण कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, उसका विरोध होना ही चाहिए। लेकिन इसके



लिए हथियारों का सहारा लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

विषमता के विरुद्ध और समानता के पक्ष में खड़ा होना गुलत नहीं है। राष्ट्रपिता बापू हमें रास्ता दिखा गए थे। अहिंसा के उस रास्ते पर चलकर हमने आज़ादी ली, सारी दुनिया ने गांधी के इस चमत्कार को देखा और सराहा। यदि आज हम हिंसा की राह पर चलकर सफलता पाने की सोच का विरोध करते हैं, तो इसे दुनिया को भारत की एक देन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसीलिए जब हिंसक तरीकों से कुछ करने या पाने की हिमायत होती है, तो भारत की जनता स्वाभाविक रूप से उसकी भर्त्सना करती है। यह इस देश का मानस है। बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे महापुरुषों ने अहिंसा को इस सोच को खाद और पानी दिया है। इसलिए जब उपलब्धियों की इस राह के पक्ष में कोई बात कही जाती है, तो भारत की जनता का समर्थन अनायास ही उसे मिल जाता है। पर यहीं पर इस बात का भी ध्यान रखा जाना

जरूरी है कि हमारा भारत विवेक और विमर्श की नीति में विश्वास करता है। जिस जनतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपने लिए स्वीकारा है, उसमें अपनी बात कहने के अधिकार के साथ-साथ दूसरे के अपनी राय

अथवा 'अर्बन नक्सली'। इस तरह के जुमले चर्चा का विषय तो आसानी से बन जाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से कुछ तात्कालिक लाभ भी मिल सकता है, पर जुमलों की राजनीति बहुत दूर तक नहीं ले जाती। 15



अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने लगभग अस्सी मिनट के भाषण में बहुत कुछ कहा था। उस सब पर देश में चर्चा होनी चाहिए थी। वस्तुतः आज़ादी की वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण अपनी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं को देश के सामने रखने वाला होना चाहिए। उसे राजनीतिक विरोधियों पर वार करने के हथियार के रूप में काम लेना उचित नहीं है।

प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा यह भी थी कि वे देश की वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए युवाओं, किशोरों और बच्चों के भी आलोड़न के बारे में कुछ ठोस विचार रखते। जंतर-मंतर पर आयोजित युवाओं का चल रही धांधली, उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रकरण को अपने भाषण का विषय बनाएंगे। पर, दुर्भाग्य से, यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ महम परिभाषित भी कर देंगे। यह विशेषण उतना ही भ्रामक है, जितना 'टुकड़े-टुकड़े गैंग'



शिवनारायण सारवदेव
थाला हर नागरिक एक तरह से निशाने पर था।

अपनी सरकार के किए-अनकिए पर सवाल उठाना हर नागरिक का अधिकार है—और कर्तव्य भी। नागरिक की यह जागरूकता जनतंत्र की सफलता की शर्त भी है और इस बात का प्रमाण भी कि देश में जनतांत्रिक मूल्य जीवित हैं। ऐसे में दिमागी नक्सली जैसा जुमला उछालकर एक तरह से भ्रम की स्थिति ही पैदा की गई है। सोचने की क्षमता को मनुष्य के अस्तित्व से जोड़कर डेकार्त ने एक मानक स्थापित कर दिया था। सोचने-समझने वालों को नक्सलवाद जैसी हिंसक परिकल्पना से जोड़कर उस मानक को ही नकारा गया है। कुछ सोचकर करने वाला ही कुछ बेहतर कह सकता है और कुछ बेहतर कहकर ही व्यक्ति समाज को बेहतर बनाने में कुछ योगदान कर सकता है। आज़ादी की वर्षगांठ जैसे अवसर नेतृत्व और जनता दोनों के लिए अपनी उपलब्धियों और कमियों का लेखा-जोखा करने के मौके होते हैं। इस लेखे-जोखे को जुमले में उछलकर कुछ खोया ही जा सकता है, पाया नहीं। भाषणों में ऐसे जुमले अच्छे लग सकते हैं, पर ये देशहित के लिए अच्छे होते नहीं।

सच कहें तो जुमले से बात बनती नहीं। बात बनाने के लिए स्पष्ट बात करना जरूरी है। बहुत कुछ है हमारे पास अपने देश की उपलब्धियां गिनाने के लिए, पर इससे कहीं अधिक उपलब्धियों की आवश्यकता है हमें। सबसे बड़ी और जरूरी उपलब्धि साथ मिलकर आगे बढ़ने की है। यह काम अपनी बात कहकर ही पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए दूसरे की बात सुननी भी जरूरी होती है—और समझनी भी। किसी को भी नक्सली कहना मुश्किल नहीं है, पर नक्सली सोच वाला कहकर हम एक तरह से उसे हाथ पकड़कर साथ चलने के अवसर से ही वंचित कर रहे होते हैं। अस्वीकार्य है यह स्थिति।

एनालॉग पनीर को लेकर उपभोक्ताओं में असमंजस

देश में एक अजीब विरोधाभास खुलकर सामने आया है। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर को कभी गैरकानूनी नहीं उठराया, बल्कि उसे बनाने और बेचने की छूट दी, बस इतनी शर्त रखी कि पैकेट पर साफ-साफ लिखा हो कि यह असली दूध से नहीं बना है। इसके बावजूद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, जबकि दूसरे

इसके निर्माण और बिक्री पर आज भी कोई रोक नहीं है। यही उलझन अब उपभोक्ताओं से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की चिंता का विषय बन गई है। एनालॉग पनीर देखने, स्वाद और बनावट में बिल्कुल असली दूध के पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसे बनाने में दूध की चर्बी या दूध के प्रोटीन की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च, सोया या मटर के प्रोटीन और चिपकाने वाले पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं-कहीं तो सोडा और वनस्पति घी से नकली दूध और फेंच चॉक यानी सेलखड़ी से नकली मावा तक तैयार किया जा रहा है। इसकी लागत असली पनीर से कहीं कम आती है, इसलिए होटल, ढाबों, रेस्तरां और खानपान के बड़े कारोबार में इसका खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। समस्या तब पैदा होती है जब इसे उसी कीमत पर, बिना किसी सूचना के, असली दूध के पनीर के नाम पर बेचा जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते आए हैं कि इस तरह के उत्पादों में मिलने वाली औद्योगिक चर्बी हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है और इससे शरीर को कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं मिलता। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि इस तरह की औद्योगिक चर्बी का कोई ज्ञात स्वास्थ्य लाभ नहीं है। इसके नियमित सेवन से पेट में संक्रमण, अम्लता, यकृत पर बुरा असर और खराब वसा का स्तर बढ़ने जैसी शिकायतें

सामने आ रही हैं। साथ ही इसमें असली दूध के मुकाबले प्रोटीन और कैल्शियम कम, जबकि सोडियम और शोधित स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे उपभोक्ता कीमत

तो दूध के पनीर जितनी चुकता है, लेकिन पोषण उतना नहीं पाता।

केंद्र सरकार का रुख शुरू से ही सतर्क रहा है। उसने इसे पूरी तरह हानिकारक मानने से इनकार किया है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसके उत्पादन पर कभी रोक नहीं लगाई गई। महाराष्ट्र की पहल के बाद केंद्रीय प्राधिकरण ने एक परिपत्र जरूर जारी किया, जिसमें होटलों को अपनाने भोजन-सूची में यह बताना अनिवार्य किया गया कि इस्तेमाल हो रहा पनीर असली है या एनालॉग। लेकिन व्यवहार में यह नियम बाजार में बहुत कम ही लागू होता दिखा, क्योंकि खुले बाजार में बिना किसी सूचना

के यह उत्पाद खपता रहा।

यही वजह रही कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र के नरम रुख से आगे बढ़कर सख्त कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में तीस जुलाई को

कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं होगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम ब्रेक माइन कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा। इस को उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां

कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं होगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम ब्रेक माइन कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा। इस को उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के

साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां

कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं होगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम ब्रेक माइन कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा। इस को उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के

साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां

कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं होगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम ब्रेक माइन कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा। इस को उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां



पंकज वासुंदी

कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं होगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम ब्रेक माइन कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा। इस को उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां

कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं होगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम ब्रेक माइन कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा। इस को उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां

ई-स्कूटी में धमाके से घर में लगी आग

माही की गूंज, रतलाम।

विंध्यावासिनी कॉलोनी में बुधवार तड़के करीब 4 बजे घर के अंदर रखी ई-स्कूटी में अचानक आग लगने के बाद धमाका हो गया। कुछ ही देर में आग पूरे कमरे और मकान में फैल गई। हादसे में कमरे में सो रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 36 वर्षीय बिंदु कुंवर और उनकी 16 वर्षीय बेटी अंतिम करीब 60 फीसदी झुलस गईं। दोनों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बड़ी बेटी विजयलक्ष्मी हादसे में बाल-बाल बच गई।

पहले गैस टंकी का बटन बंद किया, फिर छत के रास्ते निकलीं

बड़ी बेटी विजयलक्ष्मी ने बताया कि परिवार रात में करीब 8 से 8.30 बजे तक सो जाता है और करीब 9 बजे तक मोबाइल चलाता है। बुधवार सुबह करीब 4 बजे उसकी नींद खुली। उठकर देखा तो स्कूटी में आग लगी थी। उसने सबसे पहले पीछे रखी गैस टंकी का बटन बंद किया। आगे भी गैस टंकी रखी थी। इसके बाद वह ऊपर का गेट खोलने के लिए दौड़ी।

इसी दौरान छोटी बहन डरकर पीछे वाले कमरे में



चली गई। विजयलक्ष्मी ऊपर से वापस आई तो मां उसे लेने पीछे गई। इसी दौरान आग अचानक तेज हो गई। विजयलक्ष्मी ने बताया कि मां और छोटी बहन को आग से झुलसते हुए बाहर आते देखा तो दोनों का हाथ पकड़ और किसी तरह छत पर पहुंचीं। वहां से पड़ोसी की छत पर जाकर नीचे उतरी और घर से बाहर निकलीं। विजयलक्ष्मी के पैर में मामूली चोट आई है, जबकि मां और छोटी बहन गंभीर रूप से झुलस गईं।

सोने से पहले निकाला था चार्जिंग प्लग

विजय लक्ष्मी ने बताया कि रात में सोने से पहले ई-स्कूटी का चार्जिंग प्लग निकाल दिया था। ऐसे में समझ नहीं आया कि अचानक आग कैसे लगी। हादसे के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था। एक चाबी छोटी बहन के गले में थी और दूसरी मशीन पर रखी थी। घबराहट और अंधेरे के कारण छोटी बहन चाबी लेकर दरवाजे

तक नहीं आ सकी। इसलिए छत का गेट खोलकर उसी रास्ते से तीनों बाहर निकलीं।

10 दिन पहले खरीदी थी ई-स्कूटी

बिंदु कुंवर के जीजा वीरेंद्र सिंह के अनुसार, परिवार ने करीब 10 दिन पहले माणक चौक स्थित शोरूम से 85 हजार रुपए में नई ई-स्कूटी खरीदी थी। रात में स्कूटी चार्जिंग पर नहीं लगी थी। तड़के अचानक उसमें धमाका हुआ और देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ई-स्कूटी पूरी तरह जलकर लोहे के ढांचे में बदल गई। घर का पूरा सामान जल गया, वहीं कूलर और पंखे भी पिघल गए।

दमकल विभाग मौके पर

आग लगने के बाद पड़ोसियों ने भी मदद की। घर में रखी रसोई गैस की टंकी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नगर निगम की दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पड़ोसियों का आरोप है कि बार-बार कॉल करने के बावजूद करीब डेढ़ घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची।

इसके बाद घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया। दीनदयालनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि चार्जिंग पर नहीं लगी ई-स्कूटी में आग किस वजह से लगी और धमाका किन परिस्थितियों में हुआ।

समारोह के दौरान एलईडी स्क्रीन और बिजली केबल में आग से मची अफरा-तफरी



आगर मालवा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के संदेश वाचन के बीच अचानक एलईडी स्क्रीन और बिजली केबल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बच्चे और आम लोग मौजूद थे। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।

लगातार बारिश के बीच हुई इस घटना ने विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गनीमत रही कि समय रहते बिजली स्प्लाई बंद कर दी गई और बड़ा हादसा टल गया।

स्क्रीन से जुड़े बिजली केबल में अचानक आग लग गई

मुख्यमंत्री के संदेश वाचन का प्रसारण एलईडी स्क्रीन के जरिए किया जा रहा था। इसी दौरान स्क्रीन से जुड़े बिजली केबल में अचानक आग लग गई और धुआं उठने लगा। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। हालांकि प्रशासन ने तत्काल बिजली स्प्लाई बंद कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

ध्वजारोहण के समय से ही लगातार बारिश हो रही थी

घटना ने समारोह की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ध्वजारोहण के समय से ही लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में विद्युत उपकरणों और केबल की सुरक्षा, इंसुलेशन और अर्थिंग की जांच बेहद जरूरी थी। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका है, लेकिन बारिश के बीच सुरक्षा इंतजामों की पूर्ण जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि तकनीकी खराबी के साथ प्रशासनिक लापरवाही भी इसकी वजह बनी या नहीं।

गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ

फिलहाल राहत की बात यह है कि समय रहते बिजली स्प्लाई बंद कर दी गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने भविष्य में ऐसे आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान

माही की गूंज, मंदसौर।

संत शिरोमणि रविदास जी की 650 वी जन्म जयंती के अवसर पर राज्य शासन के निर्देश अनुसार मंदसौर जिले में भी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला पंचायत सभा कक्ष में बुधवार को आयोजित बैठक में विचार विमर्श कर यात्रा आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया, यात्रा की रूपरेखा तय की गई। उक्त बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला योजना समिति के सदस्य राजेश दीक्षित, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, जिला संयोजक जनजातीय विभाग श्रीमती अंगूर बाला भगौर, महिला बाल विकास अधिकारी सुश्री अंकिता पंड्या, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष राम अटेला, शिवराज सिंह राणा, विजय सुराणा, महेश जूनावाल, विनय दुबेला, जीवन शर्मा, अंकित सोनी आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने जिले में यात्रा के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंप कर निर्देशित किया है।



जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में बताया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तरीय कार्यक्रम 20 अगस्त को मंदसौर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रातः 10:00 बजे से आयोजित होगा जहां कलश वंदन तथा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके बाद पावन कलश, कलश रथ में स्थानीय रविदास मंदिर तथा ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। यात्रा के अंतर्गत 20 अगस्त से 10 सितंबर तक निर्धारित मार्गों पर कलश रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा मार्ग, पड़ाव, समय सारणी तथा स्थानीय कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस दौरान जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय तथा चिन्हित स्थानीय मंदिरों में विविध स्वरूप के आयोजन होंगे।

संकल्प तथा अन्य स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसमें स्थानीय संतो गुरुजनों समाज के प्रतिनिधियों तथा नागरिकों की सहभागिता रहेगी। इस दौरान 31 अगस्त तक संत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत संतों एवं गुरुओं को अभियान के उद्देश्य एवं गतिविधियों से अवगत कराते हुए विभिन्न सामाजिक समरसता कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान राजेश दीक्षित द्वारा जिले में अभियान एवं यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा उपस्थित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व के बारे में बताया गया। राम अटेला ने भी सफलता पूर्वक किए जानेवाले आयोजन के संबंध में बताया।

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने परियोजना अधिकारी (वाटरशेड) महेश कुमार चौबे की सविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। उनके जांच अवधि के 50 प्रतिशत मासिक पारिश्रमिक को भी स्थायी रूप से राज्य शासन के पक्ष में राजसात किया गया है। यह निर्णय शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, उदासीनता और पदीय कर्तव्यों के प्रति अनिच्छा के कारण किया गया। इस आदेश के जारी होने के बाद जिला पंचायत में हड़कंप मच गया है। आदेश जारी करने वाली रतलाम

जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन सख्त और कड़क अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इस आदेश के बाद दावा किया जा रहा है, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास में किए जा रहे गोलमाल सहित कमजोर काम करने वाले अन्य सविदा अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।

रतलाम जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने बताया महेश कुमार चौबे को वर्ष 2017 से 2024 तक कुल 42 कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे, लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई सुधारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन

समिति की बैठक में भी उनके कार्य में सुधार न होने पर सविदा समाप्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। एक स्वतंत्र जांच समिति ने अभिलेखों की जांच के बाद महेश कुमार चौबे को शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपूर्ण नस्त्रियों के संचालन और शासकीय प्रक्रियाओं के उल्लंघन का स्पष्ट दोषी पाया।

यह गड़बड़ भी की चौबे ने

रतलाम जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने बताया इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिना सक्षम

प्रेमी को घर में देख भड़का पिता

माही की गूंज, रतलाम।

औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर नाबालिग लड़की से मिलने उसके घर पहुंचे युवक पर उसके पिता ने कांच की बोतल फोड़कर हमला कर दिया। आरोप है कि पिता ने बोतल के टूटे हिस्से से युवक के गले पर वार किया। गंभीर रूप से घायल युवक को डायल-112 की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसके गले पर करीब 20 टांके लगाए गए। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई गई है।

घर में युवक को देख भड़का पिता

जानकारी के अनुसार बिरियाखंडी निवासी 20 वर्षीय समीर पुत्र शमी कुंशैरी मंगलवार को 16 वर्षीय नाबालिग से मिलने उसके घर पहुंचा था। उस

समय उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। इसी दौरान माता-पिता अचानक घर लौट आए। घर में युवक को देखकर नाबालिग के पिता नाराज हो गए और दोनों के बीच विवाद हो गया।

कांच की बोतल से गले पर किया वार

आरोप है कि विवाद के दौरान नाबालिग के पिता ने घर में रखी कांच की बोतल फोड़कर उसके टूटे हिस्से से समीर के गले पर वार कर दिया। हमले में युवक के गले के बीचों-बीच करीब 7मिमी सेंटीमीटर का घाव हुआ। चिकित्सकीय जांच में दो छोटी रसें कटने की बात भी सामने आई है।

नाबालिग ने प्रेमी बताया

घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और डायल-112 को सूचना दी।

पुलिस ने घायल युवक को डायल-112 वाहन से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। घटना के बाद नाबालिग भी मेडिकल कॉलेज पहुंची। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में उसने युवक को अपना प्रेमी बताया और उसके पिता पर कांच की बोतल से हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार दोनों करीब तीन साल से एक-दूसरे को जानते हैं। घायल युवक के बयान फिलहाल दर्ज नहीं हो सके हैं।

मामले की जांच जारी

एसआई ध्यानसिंह सोलंकी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नाबालिग के बयान लिए जा रहे हैं। घायल के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फोरलेन पर काल बनकर दौड़ा अज्ञात वाहन

माही की गूंज, मंदसौर।

बायडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां सड़क किनारे पैदल जा रहे एक युवक को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क से कई फीट दूर जा गिरा और लहलुहान हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक अपने वाहन सहित अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफूचकर हो गया।

स्थानीय लोगों और राहगीरों की मुस्तेदी से घायल युवक को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल युवक के सिर से लगातार बहते खून को रोकने के लिए डॉक्टरों को करीब 9 टांके लगाने पड़े। युवक की नाजुक हालत और गहरे जखमों को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत मंदसौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां फिलहाल उसका सघन उपचार जारी है।

इधर, हादसे की सूचना मिलते ही बायडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर तफतीश शुरू कर दी है। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार वाहन का सुराग लगाया जा सके। पुलिस का दावा है कि आरोपी चालक को जल्द ही दबोच लिया जाएगा।

कलेक्टर ने निर्माणाधीन आलू-प्याज मण्डी का निरीक्षण किया

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने आज शाजापुर तहसील के ग्राम लाहौरी बल्डे पर निर्माणाधीन आलू-प्याज मण्डी परिसर का भ्रमण कर निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। कलेक्टर सुश्री बाफना ने निर्देश दिए कि किसान हित को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण कराये, ताकि आगामी सीजन में किसानों को नई मंडी का लाभ मिल सके।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने टीन शेड निर्माण, सड़क मार्ग, विद्युत की समुचित व्यवस्था, कार्यालय भवन, प्रवेश द्वार, कंटीन, शौचालय, पेयजल एवं पार्किंग स्थल की व्यवस्था का निरीक्षण कर उक्त सभी कार्यों की गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री बाफना ने संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराए।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने मण्डी सचिव को मण्डी व्यापारियों की बैठक लेकर बैंक शाखा स्थापित करने की कार्यवाही करने एवं मण्डी में अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सुझाव लेने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने मण्डी परिसर में सोर्टिंग/ग्रेडिंग स्थापित कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजने के भी निर्देश दिये।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने मण्डी सचिव को मण्डी परिसर में पौधारोपण कराने, तौल कांटा लगवाने, पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति कराने सहित अन्य आवश्यक निर्देश भी दिये। इस अवसर पर उपसंचालक कृषि आरएल जामरे, मंडी सचिव मोहनसिंह मालवीय, अशोक जोशी, महाप्रबंधक उद्योग प्रकाश कुमार इन्दौर भी उपस्थित थे।



एमसीएच में दो साल बाद लिफ्ट चालू

माही की गूंज, रतलाम।

अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिलों तक आने-जाने में हो रही अत्यधिक असुविधा से अब बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई (एमसीएच) में पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी मुख्य लिफ्ट को मरम्मत के बाद अब फिर से संचालित कर दिया है।

लिफ्ट के बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता था, जो विशेषकर शारीरिक रूप से कमजोर और गंभीर रोगियों के लिए बेहद कष्टप्रद था। सिविल सर्जन एपी सिंह के निरंतर प्रयासों के चलते इस महत्वपूर्ण समस्या का तत्काल संज्ञान लिया गया। उनके निर्देश पर लिफ्ट की आवश्यक तकनीकी जांच की गई, सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया और समुचित रखरखाव कार्य पूर्ण करने के बाद इसे मरीजों व उनके परिजनों के लिए विधिवत शुरू कर दिया गया है।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में हुआ कार्य

सिविल सर्जन एपी सिंह ने बताया कि

कलेक्टर अजय कटसरिया के मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने स्वीकार किया कि लिफ्ट का लंबे समय से बंद रहना मरीजों के लिए बेहद कष्टदायी था, जिसे कलेक्टर के निर्देशानुसार सहयोग से सुचारु किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए लिफ्ट के नियमित रखरखाव की स्थायी व्यवस्था की है।

लिफ्ट का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार करें

लिफ्ट चालू होने से अब स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के माध्यम से मरीजों के आवागमन में काफी सुगमता आएगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में भी त्वरित सेवा मिल सकेगी। अस्पताल प्रबंधन ने आमजन और मरीजों से आग्रह किया है कि वे लिफ्ट का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार करें एवं



अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

मरीजों के लिए लिफ्ट का महत्व

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में लिफ्ट का चालू होना मरीजों के लिए अपूर्व सुविधा है। गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर रोगियों को ऊपरी मंजिलों पर ले जाने में यह

सहायक होती है। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी लिफ्ट अत्यंत आवश्यक है। यह मरीजों के साथ-साथ अस्पताल स्टाफ और परिजनों के शारीरिक श्रम को कम करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। लिफ्ट सुविधा से अस्पताल परिसर में आवागमन सुगम और सुरक्षित बनता है।

ठेले पर हुए विवाद में युवक की हत्या, एक ही परिवार के पांच लोगों को जेल

माही की गूंज, खंडवा।

मांधाता थाना क्षेत्र के भोंगावा गांव में अंडे के ठेले पर हुए विवाद के बाद युवक की मौत के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी के न्यायालय ने एक ही परिवार के पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर कुल 1 लाख 2 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। निर्णय के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।

अभियोजन के अनुसार 28 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे 35 वर्षीय लोकेंद्र करजरे गांव में मुकेश की दुकान के पास लगे अंडे के ठेले पर खड़ा था। इसी दौरान रवि धावें वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और गाली-गलौज हुई। इसके बाद रवि वहां से चला गया तथा लोकेंद्र को देख लेने की धमकी दी।

कुछ समय बाद रवि अपने पिता सेवकराम धावें, मां

शांताबाई, भाई बब्लू धावें तथा रिश्तेदार ताराचंद उर्फ छोटू के साथ वापस आया। आरोपियों ने मिलकर लोकेंद्र को धेर लिया और लात-धुंसों से मारपीट की। गंभीर चोट लगने से लोकेंद्र जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया।

परिजन और ग्रामीण उसे उपचार के लिए सनावद सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव परीक्षण में सामने आया कि मारपीट के कारण उसका फेफड़ा फट गया था, जिससे शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसके महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया।

घटना के बाद मांधाता पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूरी की तथा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।

बचाव पक्ष ने आरोपियों की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए दंड में नरमी की मांग की, लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सामूहिक हिंसा और मारपीट

जैसे मामलों में दोषियों को राहत देना उचित नहीं होगा।

यायालय सेवकराम धावें, रवि धावें, शांताबाई धावें, बब्लू धावें तथा ताराचंद धावें को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त धारा 147 के तहत सभी को एक-एक वर्ष का कारावास तथा 500-500 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि में से नियमानुसार



में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिनी भाटे ने पैरवी की।

समान नागरिक संहिता विधेयक के विरोध में ज्ञापन

माही की गूंज, खरगोन।

समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक के विरोध में बुधवार दोपहर मुस्लिम सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विधेयक को तत्काल वापस लेने और इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की।

प्रतिनिधियों ने कहा कि विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून पर व्यापक चर्चा जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रपति से विधेयक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता विधेयक संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। उनका कहना है कि यह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के विपरीत है और इसके लागू होने से मुस्लिम समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

प्रतिनिधि अल्ताफ आजाद ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में दिए गए अधिकारों के विपरीत है और इससे संविधान की मूल भावना प्रभावित होगी।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुफ्ती एजाज, आसिफ प्रिंस, अल्ताफ आजाद, आशमा शेख सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।



परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों ने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, सेंधवा।

वीर बलिदानी खाज्या नायक शासकीय महाविद्यालय के हिंदी साहित्य तृतीय सेमेस्टर के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने क्रातिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगोन से परिणाम में सुधार करने की मांग की है।



छात्रों का आरोप है कि हाल ही में जारी परीक्षा परिणाम में कई विद्यार्थियों को बहुत कम अंक दिए गए हैं। विशेष रूप से 'आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास' विषय में कई विद्यार्थियों को शून्य अंक दिए गए हैं, जबकि कुछ विद्यार्थियों के परिणाम में एटीकेटी दर्शाई गई है।

छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने के साथ अंकों की गणना और ऑनलाइन व्यवस्था में अंक दर्ज किए जाने की प्रक्रिया की भी दोबारा जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी मानवीय या

तकनीकी त्रुटि को तत्काल सुधारकर संशोधित परिणाम जारी किया जाना चाहिए।

मामले में आदिवासी छात्र संगठन ने भी विद्यार्थियों की मांगों का समर्थन किया है। संगठन के अध्यक्ष अर्जुन डुड्डे, उपाध्यक्ष प्रकाश सोलंकी सहित कई छात्र मौके पर मौजूद रहे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि परीक्षा परिणाम में जल्द सुधार नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे।

19 दिन में शक्कर 18 रुपए महंगी

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी में शक्कर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को थोक बाजार में शक्कर का भाव करीब 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। किराना व्यापारियों के अनुसार महज 19 दिनों में शक्कर की कीमत में करीब 18 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते दाम का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

किराना व्यापारी कमल गोले के अनुसार 1 से 19 अगस्त के बीच शक्कर के भाव में करीब 18 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। 1 अगस्त से पहले शक्कर करीब 42 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। व्यापारियों का कहना है कि यदि तेजी का यह दौर जारी रहा तो खुदरा बाजार में शक्कर का भाव 70

रुपए प्रति किलो से ऊपर जा सकता है, जबकि थोक बाजार में कीमत 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना है।

शक्कर के साथ गुड़ के दाम में भी तेजी आई है। तीन दिन पहले गुड़ 50 से 52 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 60 से 62 रुपए प्रति किलो हो गया है। व्यापारियों के अनुसार शक्कर के दाम बढ़ने का प्रमुख कारण कम बारिश को माना जा रहा है। गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त बारिश नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। गन्ने की उपलब्धता और चीनी उत्पादन को लेकर बाजार में चिंता बढ़ने से कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है।

व्यापारियों के अनुसार अन्य देशों से आने वाली शक्कर की उपलब्धता पर भी मौसम का असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में बाजार

पर दिखाई दे सकता है।

शक्कर के बढ़ते दाम का असर मिठाई कारोबार पर भी पड़ने की संभावना है। आने वाले त्योहारों और शादी के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। शक्कर के अलावा काजू, सूखे मेवे और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के दाम भी बढ़ेंगे। ऐसे में मिठाइयों की कीमत में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना व्यापारियों ने जताई है। बड़वानी में प्रतिदिन कई किटल शक्कर की खपत होती है। घरों के अलावा होटल, भोजनालय, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य कारोबार में भी बड़ी मात्रा में शक्कर की जरूरत होती है। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर कीमतों में और तेजी आने की आशंका है।

बड़वानी में ऑनलाइन दाढ़ी-मूंछ प्रतियोगिता संपन्न

माही की गूंज, बड़वानी।

बीआरओ दाढ़ी एवं मूंछ क्लब द्वारा आयोजित ऑनलाइन दाढ़ी-मूंछ प्रतियोगिता 18 अगस्त की रात संपन्न हुई। प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर दाढ़ी और मूंछ की अलग-अलग शैलियों और रूप का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता के लिए 15 जून से निःशुल्क पंजीयन शुरू किया गया था, जो 4 जुलाई तक चला। मुकाबले में दाढ़ी-मूंछ की कुल 10 अलग-अलग श्रेणियां रखी गई थीं, जिनमें प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का

प्रदर्शन किया।

आयोजक शुभम जाट ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले दाढ़ी-मूंछ के शौकीनों को बिना यात्रा और अतिरिक्त खर्च के अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना था। आमतौर पर दाढ़ी-मूंछ की प्रतियोगिताएं किसी एक स्थान पर आयोजित होती हैं, जिससे कारण प्रतिभागियों को आने-जाने में समय और काफी खर्च करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए क्लब ने ऑनलाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की।

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का ऑनलाइन निरीक्षण और मूल्यांकन

किया गया। राहुल थानवी, चंद्र प्रकाश व्यास, सुरेंद्र सिंह चावड़ा, रविचंद्र और टीएस-एपी दाढ़ी क्लब के रुपेश सहित निर्णायक दल के सहयोग से अलग-अलग श्रेणियों में विजेताओं का चयन किया गया।

प्रतियोगिता में कुल 30 विजेताओं का चयन किया गया। क्लब की ओर से विजेताओं को ऑनलाइन पुरस्कार राशि प्रदान की गई। विभिन्न श्रेणियों में 1901, 1101 और 5001 रुपए सहित अलग-अलग पुरस्कार राशि रखी गई थी।

आयोजन को सफल बनाने में बीआरओ दाढ़ी एवं मूंछ क्लब के

संस्थापक शुभम जाट और नरेंद्र चौधरी, निदेशक अभिषेक चंदेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप दिव्यवीर तथा सदस्य हरीश राठौर, दीपक मलहार और महेश मेहता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आयोजक टीम ने बताया कि प्रतियोगिता की सबसे बड़ी सफलता देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। ऑनलाइन मंच के माध्यम से दाढ़ी-मूंछ के शौकीनों को एक साथ जोड़ने का यह प्रयास भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी पहचान, शैली और जुनून का प्रदर्शन किया।



हर मौसम में निर्बाध भरोसेमंद सड़कों की जरूरत

उत्तराखंड में वर्षों पहले जिस सड़क परियोजना की चर्चा 'ऑल वेदर रोड' के नाम से शुरू हुई थी, वह अब 'चारधाम मार्ग' के नाम से अधिक जानी जाती है। लेकिन सवाल नाम का नहीं, उसके उद्देश्य और परिणाम का है। यदि यह सचमुच ऑल वेदर रोड है, तो बार-बार, बीसियों स्थानों पर मौसम की मार से अवरुद्ध होना इसके दावे पर सवाल खड़ा करता है। मूल सवाल है- क्या सड़क केवल चौड़ी और नई बनी है, या वास्तव में हर मौसम में भरोसेमंद आवागमन के योग्य भी हुई है?

चारधाम तक ही क्यों? जब सड़कों का निर्माण जनता से वसूलें गए करों और रोड टैक्स जैसे साधनों से होता है, तो हर सड़क का हर मौसम में उपयोगी व भरोसेमंद होना जनता का अधिकार है; सड़कें किसी सरकार की भीख नहीं। गांवों में ऑल वेदर मार्ग किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इससे आलू, सेब जैसे उत्पाद समय पर बाजार पहुंचेंगे व खराब होने की आशंका घटेगी। गांवों की सड़कों को ऑल वेदर बनाने का लक्ष्य कई पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में पहले से रहा है।

सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से भी ऑल वेदर रोड की आवश्यकता है और उत्तराखंड में यह प्रमुख प्राथमिकताओं में हो। धार्मिक चारधाम यात्रा के नाम पर भले ही इसे चारधाम मार्ग कहा गया हो, पर चारधाम यात्रा वर्ष में करीब छह माह, कपाट खुले रहने की अवधि में ही होती है व इसके लिए फोर-लेन सड़कें अनिवार्य नहीं। किसी भी मौसम में सड़कों पर सुरक्षित और सुगम आवागमन केवल

सड़क की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि नागरिकों और कर्मचारियों के आचरण व कार्य-संस्कृति पर भी निर्भर करता है। बिजली, पानी, सीवर या टेलीफोन लाइनों के लिए बार-बार नई सड़कों को खोदना, उन पर रेत-बजरी बिखेरना अथवा निर्माण सामग्री डम्प करना आम बात है। इससे वाहन फिसलने जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। यदि हम स्वयं सड़कों पर ऐसी सामग्री बिखेरें, जो बरसात में फिसलन या आंधी में धूल-गुबार का कारण बने, तो ऑल वेदर रोड का लाभ कितना मिल पाएगा? ओस या बर्फ जमने पर सड़क सुरक्षित रहने के बावजूद पैदल चलना भी कठिन हो जाता है।

पहाड़ों में हर साल आपदाओं से टूटने वाले पुल-पुलिये समय पर ठीक नहीं हो पाते। जर्जर ट्रॉलियों और पेड़ों के तनों के सहारे नदी-नाले पार करना आज भी जोखिम भरा है; बच्चों सहित ग्रामीणों के घायल होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हजारों करोड़ रुपये की चारधाम ऑल वेदर रोड का लाभ भी तभी मिलेगा, जब मरीज, किसान और आम नागरिक अपनी सड़क,

फगडंडी और पुल के जरिए उसके मुहाने तक पहुंच सकें। टिहरी बांध के जलाशय बनने के बाद



प्रतापनगर, केदार त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों, यमकेश्वर-ढांगू, गुप्तकाशी और कुमाऊं के अनेक गांवों में यह समस्या आज भी बनी हुई है। बरसात में बच्चों का स्कूल पहुंचना और मरीजों अथवा प्रसव के निकट महिलाओं को मोटर मार्ग तक लाना तक कठिन हो जाता है। कई सम्पर्क मार्ग

ठीक होने के बावजूद वाहन-विहीन रहते हैं। सवाल इसलिए केवल ऑल वेदर रोड का नहीं,

बल्कि गांवों को स्कूल, अस्पताल और मुख्य मार्गों से हर मौसम में जोड़ने वाले भरोसेमंद सम्पर्क तंत्र का है।

सवाल है कि ऑल वेदर रोड से पहले गांवों में ऑल वेदर स्कूलों, अस्पतालों और मुख्य मार्गों तक पहुंच सरकारों की प्राथमिकता क्यों नहीं है?

असल में जरूरत केवल ऑल वेदर रोड की नहीं, बल्कि हर मौसम में उपयोगी और सुरक्षित सम्पूर्ण सड़क-सम्पर्क तंत्र की है। सड़क पर पर्याप्त रोशनी पर भी खास ध्यान नहीं। राहगीर चाहता है कि उसकी सड़क, फगडंडी या पुल किसी भी मौसम में बाधित न हो। फ्लाईओवर और पुलों की सुरक्षा कार्डिफो भी चिंता से परे नहीं; पुलों के गिरने, भूस्तर और अवैध खनन से उनके स्तंभों व सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के मामले इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं।

ऑल वेदर रोड का सड़क की चौड़ाई से सीधा संबंध नहीं है। संकरी फगडंडी भी ऑल वेदर हो सकती है, यदि वह हर मौसम में सुरक्षित और आवागमन योग्य रहे। हां, चौड़ी सड़क पर मलबा गिरने की स्थिति में उसके

सम्पर्क मार्गों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जैसे मुख्य नदी के लिए सहायक नदी महत्वपूर्ण है, वैसे ही सड़कों के लिए सम्पर्क मार्ग अहम हैं। सभी सड़कों के सुरक्षा कार्डिफो भी चिंता से परे नहीं; पुलों के गिरने, भूस्तर और अवैध खनन से उनके स्तंभों व सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के मामले इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं।

ऑल वेदर रोड का सड़क की चौड़ाई से सीधा संबंध नहीं है। संकरी फगडंडी भी ऑल वेदर हो सकती है, यदि वह हर मौसम में सुरक्षित और आवागमन योग्य रहे। हां, चौड़ी सड़क पर मलबा गिरने की स्थिति में उसके

किसी हिस्से से बचकर निकलना बनिस्वत आसान होता है। पहले, खासकर फौजी वाहनों में, छोटा-मोटा मलबा हटाने को बेलक-कुदाल तक रखे जाते थे; अब स्थिति यह कि खड़े या चलते वाहनों पर सीधे मलबा गिरने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क कटान के नीचे के पेड़ों की कटाई भी जोखिमों को बढ़ा रही है।

सम्पर्क मार्गों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जैसे मुख्य नदी के लिए सहायक नदी महत्वपूर्ण है, वैसे ही सड़कों के लिए सम्पर्क मार्ग अहम हैं। सभी सड़कों के सुरक्षा कार्डिफो भी चिंता से परे नहीं; पुलों के गिरने, भू-क्षरण व भूस्खलनों को रोकने के लिए जलागम प्रबंधन का काम होना चाहिए। सड़कों की ज्योमेट्री और तात्कालिक ड्रमिंग ग्राउंड के महत्व को भी रेखांकित किया जाना जरूरी है। अन्यथा सड़क खोलने की जल्दी में सारा मलबा और बड़े-बड़े पत्थर भी नीचे लुढ़का दिए जाते हैं। यह भी कार्य-संस्कृति से जुड़ा सवाल है। सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट्स से सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों, जैसे जलस्रोत, चारा, लकड़ी और लघु वन उत्पादों के संग्रहण के पारम्परिक क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। बड़े पैमाने पर भूगर्भीय कमजोरियों के कारण जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।

न भूलें कि पहाड़ों में, और पूरे विश्व में भी, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं वालों ने, चाहे वे खनन की हों या विद्युत उत्पादन की, अपने मतलब के लिए, अपनी मशीनों की दुलाई और कई-कई पहियों वाले भारी वाहनों की आवाजाही के लिए सड़कें बनाई हैं। बेशक अहसान स्थानीय लोगों पर ही जाता जाय।



वीरेंद्र कुमार

तीन बड़े नालों का गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा

माही की गूंज, उज्जैन।

3 बड़े नाले का पानी शिप्रा में मिल रहा है, उज्जैन क्षेत्र के कुल 14 नालों में से 11 नालों को बंद करने का दावा किया गया है, लेकिन पीलियाखाल, हाटकेश्वर और भैरवगढ़ नाले आज भी बिना ट्रीटमेंट किया हुआ और जहरीला अपशिष्ट जल सीधे शिप्रा नदी में बहा रहे हैं। यह खुलासा संयुक्त समिति की रिपोर्ट में हुआ है। एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि सीवेज को शिप्रा में मिलने से रोके।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सिंहस्थ-2028 से पहले मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन को लेकर बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त समिति द्वारा एनजीटी को सौंपी गई हालिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्तमान में लगभग 85 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) सीवेज उत्पन्न हो रहा है। वर्ष 2028 में लगने वाले कुम्भ के दौरान देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह सीवेज बढ़कर लगभग 350 एमएलडी तक



पहुँचने की संभावना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सिंहस्थ-2028 से पहले शिप्रा नदी के जल को लेकर पाया कि पवित्र शिप्रा नदी के पानी में शिप्रा नदी के जल के नमूनों में वर्तमान में स्नान करने योग्य भी नहीं बचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर शिप्रा नदी

के एक बड़े हिस्से को प्रदूषित नदी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। शिप्रा नदी के जल के नमूनों में बीओडी 8 से 12 एमजी/एल पाया गया है। जबकि नियमों के अनुसार, सुरक्षित स्नान योग्य जल के लिए इसका मानक अधिकतम 3 एमजी/एल होना चाहिए। जाँच में सामने आया कि उज्जैन का सदावतल वेस्ट स्ट्रेबलाइजेशन पॉन्ड

निर्धारित बीओडी मानकों का पालन करने में पूरी तरह विफल रहा है। 3 बड़े नाले का पानी शिप्रा में मिल रहा है। उज्जैन क्षेत्र के कुल 14 नालों में से 11 नालों को बंद करने का दावा किया गया है, लेकिन पीलियाखाल, हाटकेश्वर और भैरवगढ़ नाले आज भी बिना ट्रीटमेंट किया हुआ और जहरीला अपशिष्ट जल सीधे शिप्रा नदी में बहा रहे हैं। नदी की इस दुर्दशा पर कड़ा सज्जान लेते हुए एनजीटी ने कड़े कानूनी और सुधारात्मक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सीवेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए नगर निगम उज्जैन और जिला कलेक्टर उज्जैन को सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जलस्रोत या गंदे पानी का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर नदी और नालों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रदूषण बोर्ड को तत्काल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने तथा दोषी अधिकारियों व संस्थाओं से पर्यावरण मुआवजा वसूलने के भी आदेश दिए गए हैं।

7 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मध्यप्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशानुसार जिले में 7 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को पीजी कॉलेज आलीराजपुर के ऑडिटोरियम हॉल में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का दल तैयार करना है।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित एवं पंजीकृत 125 युवा आपदा मित्र वालंटियर्स ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान आपदा मित्रों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों, राहत एवं बचाव कार्यों तथा आपदा के दौरान आमजन की सहायता करने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी।



आम्बुआ सहित समीप ग्राम बोरझाड में मनाई गई नागपंचमी

माही की गूंज, आम्बुआ।

स्नातन हिन्दू धर्म में देवी देवताओं के अलावा उनके वाहनों एवं अन्य सहयोगी तथा श्रंगारों की भी पूजा का विधान है वह भले ही वर्ष में एक बार ही क्यों न हो ती हो। मिली जानकारी के अनुसार हिन्दू देवी देवताओं के साथ उनके वाहनों आदि की पूजा की जाती है। जैसे माता अंबे के वाहन शेर, भगवान कार्तिक के मयूर, श्री गणेश के मूषक, श्री विष्णु जी के गरुण, आदि के साथ भगवान शिव के वाहन नंदी तथा उनके गले के श्रंगार विषधर नाग की पूजा सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को की जाती है। आज भी क्षेत्र में नागपंचमी के पावन अवसर पर हिंदू स्नातन धर्म के मानने वाले परिवारों ने घरों के बाहर नाग की आकृतियां बनाई जाकर तथा नाग मंदिरों एवं दीमक बार्मी जिसे सर्पों का निवास माना जाता है की विधि विधान

के साथ महिलाओं द्वारा की गई। दूध नारियल तथा विभिन्न पूजा सामग्रियों के साथ पूजा अर्चना कर क्षेत्र में तथा घर परिवारों में खुशहाली बनाए रखने हेतु प्रार्थना की गई। सुबह से लेकर दोपहर तक आम्बुआ तथा बोरझाड में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, मंदिर स्थल पर सुबह से लेकर दोपहर तक पुलिस की माकूल व्यवस्था बनी रही।



उल्लास-एक अभिनव प्रयोग

माही की गूंज, अलीराजपुर।

म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा न्यायिक अधिकारिगण, अभिभाषकगण एवं कर्मचारियों के बीच निकटता, विश्वास एवं सकारात्मक माहौल विकसित करने के उद्देश्य से “उल्लास-एक अभिनव प्रयोग” कार्यक्रम के माध्यम से पहल की गई है, जिसके अंतर्गत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती के अवसरों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु “एडवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एम्प्लॉयी वेलबीइंग” जारी की गई है।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलीराजपुर के मार्गदर्शन में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर आलीराजपुर में न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण एवं कर्मचारियों के बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक आयु वर्ग हेतु चैयरसेस, नृत्यकला, गायन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा न्यायालय परिसर में फूड स्टॉल लगाये गये। सभी प्रतियोगिताओं के बालक-बालिकाओं ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता की।

कार्यक्रम में जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया, वहीं महिला कर्मचारियों ने पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा



प्राधिकरण आलीराजपुर द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में नंदराम परमार प्रथम जिला न्यायाधीश आलीराजपुर, हिमांशु शर्मा जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट, आर.पी. सेवेतिया द्वितीय जिला न्यायाधीश आलीराजपुर, श्रीमती ज्योत्सना आर्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जय पाटीदार सचिव जि.वि.से.प्रा. एवं न्यायाधीशगण - कृष्णपालसिंह सिसौदिया, अनुराग सिंह सुमन, क्षितिज शैलेन्द्र पवार, अंशुल चन्द्रा, श्रीमती शक्ति रावत जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा जिला न्यायालय व तहसील न्यायालय के कर्मचारीगण एवं उनके बालक-बालिका व परिजन उपस्थित रहे।

प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा बालक-बालिकाओं को उत्साहवर्धन किया, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हर प्रतियोगिता हमें कठिन परिस्थितियों से निपटने, तुरंत निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने का कोशल सिखाती है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने से व्यक्ति जीवन जीने और नेतृत्व करने की कला सीख सकता है, इसलिए आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आप न केवल इसका आनंद ले रहे हैं बल्कि आप जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीख रहे हैं। प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार वितरित कर प्रोत्साहित किया गया।

ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन

माही की गूंज, आम्बुआ।

ग्राम पंचायत आम्बुआ द्वारा 19 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई तथा सदस्यों से प्राप्त सुझाओं प्रस्ताओं पर सहमति जताई गई। जिनमें स्वच्छता, पानी के अपव्यय को रोकने एवं नवीन निर्माण कार्य तथा मरम्मत के कार्यों पर सहमति के साथ ही जल समिति का बाढ़ बार गठन किया गया।

मिली जानकारी अनुसार आम्बुआ ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन के दूसरी मंजिल पर ग्राम पंचायत सरपंच रमेश रावत की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें सार्वजनिक जन हितैषी मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें प्रमुख चर्चा पुराने तथा नये बस स्टैंड पर बने सुविधा घरों की साफ-सफाई के साथ ही उनकी मरम्मत तथा गंदे पानी की निकासी व्यवस्था एवं पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अनुपयोगी पड़े सब्जी बाजार स्थल पर

दुकानों का निर्माण कर नीलामी के माध्यम से सफाई कर दिए जाने के प्रस्ताव के साथ ही, कस्बे में कचरा प्रबंधन हेतु डस्टबिन रखने तथा दो पीवीसी शौचालय जिन्हें जोबट तिराहे पर तथा एक गांधी आश्रम चौराहे के समीप रखे जाने पर सहमति जताई गई। श्री राम मंदिर प्रांगण से मुस्लिम कब्रिस्तान मार्ग के बीच बनी पुलिया को ऊंचा उठाने तथा नाली निर्माण किया जा ना प्रस्तावित है। कस्बे में शिक्षण संस्थाओं के लिए खेल मैदान तथा दशहरा मैदान हेतु जमीन हेतु प्रशासन को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया गया।



बैठक में पेय जल व्यवस्था सुधार हेतु वाई वार एक पंच के साथ एक नागरिक सदस्य के साथ जल समिति का गठन किया गया, ताकि जल वितरण ठीक से हो तथा जल का अपव्यय न हो। इस अवसर पर उप-सरपंच थानसिंह भयंडिया, सचिव उज्जवल चौहान, मोहम्मद भाई बोहरा, पूर्व उप सरपंच तथा भाजापा मंडल अध्यक्ष भरत माहेश्वरी, वरिष्ठ पत्रकार जगराम विश्वकर्मा, हुसैन बोहरा, विजय रावत, अब्दुल कादिर बोहरा, सिराज खान, अनील माली राकेश राठौड़, सारिक खान आदि अनेक ग्राम सभा सदस्य उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

माही की गूंज, रतलाम। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रतलाम, रावटी एवं ताल क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिए गए तथा मिलावट की आशंका वाले खाद्य पदार्थों को नियमानुसार जप्त किया गया।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता द्वारा रतलाम स्थित जैन प्रोडक्ट, दिलीप नगर पर कार्रवाई की गई। यहां तेज चार धाम पूजा घी के नमूने जांच हेतु लिए गए। फर्म के संचालक रितेश ने बताया कि दिल्ली से अखाद्य घी, जो केवल पूजा के लिए तैयार किया गया है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैयार करवाकर थोक में विक्रय किया जाता है। मौके पर उपलब्ध लगभग 1488 लीटर पूजा घी, जिसकी

अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपये है, जप्त किया गया तथा इसके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। स्वस्तिक टी डिपो, रतलाम पर भी कार्रवाई की गई। यहां से अरिहंत घी, मधुसूदन घी एवं चाय के नमूने जांच हेतु लिए गए। आरजी किराना, रावटी का निरीक्षण कर वास्तु घी का नमूना जांच हेतु लिया गया तथा 15 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 9 हजार रुपये है, जप्त किया गया। इसी प्रकार सिद्धार्थ ट्रेडर्स, बस स्टैंड रावटी से पुराशयौर देसी घी का नमूना लिया गया तथा 43 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 27 हजार रुपये है, जप्त किया गया। श्री कृष्ण डेयरी, रावटी से श्री रत्नागिरी घी का नमूना लिया गया तथा 75 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 31 हजार रुपये है, जप्त किया गया।

श्रावणमास में शिवजी का नित नवीन हो रहा है श्रंगार

माही की गूंज, आम्बुआ।

भगवान शिव को श्रिय मास सावन में हिन्दू स्नातन धर्मावलंबी वर्ष भर इंतजार करते हैं ताकि वे शिव आराधना कर अपना जीवन सफल बना सकें इस पूरे महीने में उपवास किया जा कर प्रतिदिन जलाभिषेक पूजा अर्चना कर शिवजी को रिझाने का प्रयास किया जा ता है। मंदिरों के पुजारी तथा भक्त प्रति दिन बाबा भोलेनाथ का आकर्षक श्रंगार प्राकृतिक सामग्रियों तथा अन्य मनमोहक सजावटी वस्तुओं से बाबा की झांकियां सजाई रहे हैं। आम्बुआ में त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन तथा हथनेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को भूत-भावन, गौरा पति शिवजी का अनुपम श्रंगार दर्शन करने आए भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है।



दूसरी कावड़ यात्रा संपन्न

माही की गूंज, बनी। ऋषभ गुप्ता

सावन मास के पवित्र महीने में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा भक्ति और अन्य कई तरह के धार्मिक आयोजन कर भोलेनाथ भगवान को श्रद्धालु प्रसन्न करने में लिन है। इसी क्रम में गांव बनी में श्री शिवाय गुप के द्वारा तीसरे सोमवार को दूसरी भव्य कावड़ यात्रा श्रृंगेर धाम के लिए निकाली गई, इस यात्रा में सर्व समाज के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कावड़ का शुभारंभ ग्राम बनी स्थित भोलेनाथ मंदिर से किया गया। सभी कावड़ियों ने बोल- बम के नारे लगाते हुए शुरुआत की, कावड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उनके ही द्वारा पुरी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया।



जनता यातायात नियमों से अनजान, प्रतिदिन 200 ई चालान बनाए जा रहे

माही की गूंज, उज्जैन।

ऐसा लगता है कि उज्जैन की जनता को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है। तभी तो प. ति दि न औसतन 200 ई चालान बनाकर लोगों को मैसेज पर भेजे जा रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 6 साल पहले शहर में स्मार्ट सिटी कंपनी ने आधुनिक इंटीग्रेटेड ट्राफिक सिस्टम लगाए थे। तब से लेकर अब तक सिग्नलों के ऊपर लगे आधुनिक सीसीटीवी कैमरों में रोजाना सैकड़ों लोग ट्राफिक के नियम तोड़ते कैद हो रहे हैं।



छात्राओं का विरोध : स्कूल स्थानांतरण टला

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन के शासकीय सराफा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छात्राओं के विरोध को देखते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तब तक स्कूल पुराने भवन में ही संचालित रहेगा।

मंगलवार को उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, विधायक अनिल जैन और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह स्कूल का दौरा करने पहुंचे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं से बातचीत की और उनकी चिंताओं को सुना।

दूरी और सुरक्षा की चिंताएं:

चार दिन पहले, छात्राओं ने स्कूल



स्थानांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जैन-जी और जैन-अल्फा की छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि महाकाल

मंदिर के पीछे स्थित मौजूदा स्कूल को दाऊदखेड़ी के सांदीपनि विद्यालय में मर्ज करने से उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने यात्रा और सुरक्षा से संबंधित

समस्याओं का भी उल्लेख किया।

छात्राओं के विरोध और उनकी मांगों की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार ने स्पष्ट किया कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पढ़ाई मौजूदा सराफा स्कूल भवन में ही जारी रहेगी।

कलेक्टर का सुरक्षा का आश्वासन

स्कूल पहुंचकर कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि उनकी पढ़ाई और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, छात्राएं इसी भवन में पढ़ेंगी। सरकार का प्रयास है कि छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन भी मिले। छात्राओं के विरोध के बाद सरकार के निर्णय से स्कूल स्थानांतरण की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

कलेक्टर तुकाराम भरसट की नाक के नीचे बीईओ ओझा और प्राचार्य प्रसाद का खेल

संभाग से रोकी गई वेतन वृद्धि का लाभ लेने की कोशिश, राज्यपाल के दौरे पर सामने आई थी बड़ी लापरवाही

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश मोहलौत

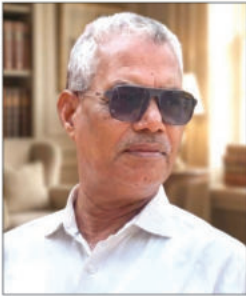
आदिवासी विकास विभाग में आने वाली योजनाओं से लेकर हर सरकारी सहायता, भवन, सामग्री, साइकिल, स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति, मध्यान भोजन से लेकर शिक्षा देने तक में लापरवाही और भ्रष्टाचार का बोल बाला है। मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर दूसरे सभी प्लेटफार्म से अनियमिता शासन-प्रशासन के पास पहुंचती है लेकिन सुधार के बजाए व्यवस्था और बिगड़ जाती है। विवादित और भ्रष्ट अधिकारियों को विकास खंड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारीया देकर विभाग का बंटोधार किया जा रहा है। यहां विभाग में पूर्व बीईओ सुमनकांत वेश्णोय से लेकर अब तक कई विभागीय हेराफेरी, फर्जी नियुक्ति, छात्रवृत्ति घोटाले सहित कई बड़े मामले पेटलावद विकास खंड को प्रदेश स्तर तक शर्मशार कर चुके हैं। राज्यपाल के पेटलावद विकास खंड में हुए प्रथम आम्रमन में प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद के कारण पूरे विभाग और कलेक्टर को शर्मशार होना पड़ा था। यहां पेटलावद के विवादस्पद प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद एक बार फिर चर्चा में है इनकी कारगुजारी का एक बार फिर नया

मामला सामने आया है।

विवादित प्राचार्य पर लगाम नहीं: बाबू, बीईओ के साथ मिलकर फिर कर दिया खेल

वैसे तो उक्त प्राचार्य अपनी विवादस्पद कार्यशैली के चलते पेटलावद से भोपाल तक चर्चित है। हाल ही में इनका एक नया मामला सामने आया है जिसमें आयुक्त इंदौर द्वारा असेंचाई प्रभाव से रोकी गई वेतन वृद्धि के आदेश को हवा में उड़ा दिया और स्थापना बाबू और एकाउंटेंट पर दबाव, प्रभाव जमाकर गलत तरीके से वेतन वृद्धि लगवा कर अवैध रूप से शासन को चुना लगाकर लाभ प्राप्त किया गया। आखिर में जब बात इस प्राचार्य पर आती है तो इस अधिकारी के किए कृत्यों का खामियाजा छोटे कर्मचारीयो को ही क्यों भुगतना पड़ता है...!

बीईओ ओझा की भूमिका भी सदिग्ध,



विवादित प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद।



खुद को बता रहे पाक साफ

इस मामले में भी खण्ड शिक्षा अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में जिनके द्वारा चुपचाप अवैध तरीके से वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। मामला जब विभाग के संज्ञान में आया तो परिणाम कारण बताओ नोटिस के रूप में सामने आया और खण्ड शिक्षा अधिकारी पेटलावद देवेन्द्र कुमार ओझा को आयुक्त इंदौर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। खैर इस मामले में भी हर बार की तरह लोपापोती कर फिर इस प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद खुद को बचाने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि प्रसाद को अपनी विभाग सेंटिंग और लक्ष्मी यंत्र की

ताकत पता है। इधर बीईओ देवेन्द्र ओझा ने पूरे मामले से अपना पल्ल झाड़ते हुए दिखाई दिए। जब उनसे इस विषय में जानकारी ली तो बीईओ ओझा ने बताया कि, वेतन वृद्धि निकालने से पूर्व सभी को पत्र जारी किया जाता है जिसमें जिनकी वेतन वृद्धि रुकी है, उनकी वेतन वृद्धि प्रकरण नहीं लगाने का कहा जाता है। लेकिन प्राचार्य प्रसाद ने वेतन वृद्धि का प्रकरण उनके कार्यालय से लगा कर भेजा था जिसके कारण भुगतान हो गया। मामला सामने आने के बाद खुद प्राचार्य प्रसाद ने लिखित में अपनी गलती के कारण भुगतान होना बता कर वेतन से वसूली करने का लिखित में विभाग को



बीईओ देवेन्द्र ओझा।

जानकारी नहीं होती है क्या? जिससे इस प्रकार की हेरा फेरी नहीं पकड़ी जाती या फिर विभाग को गुमराह कर विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ा कर उनका भुगतान कर दिया जाता है और पकड़े जाने पर भूल स्वीकार कर मामला दबा दिया जाता है?

इंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग से जारी कारण बताओ सूचना पत्र

कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास, इंदौर द्वारा देवेन्द्र ओझा, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड पेटलावद को दिनांक 20 जुलाई 2026 को नोटिस कर्मांक शिक्षा स्था./2026/ 4020 भेजा गया। आयुक्त इंदौर के

आदेश कर्मांक 395/शिकायत/2024/571 दिनांक 24 फरवरी 2024 से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेटलावद के प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद की दो वेतनवृद्धियां असेंचयी प्रभाव से रोकी गई थीं। ये दण्ड एमपी सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत दिया गया था। उस आदेश के बाद भी कार्यालय द्वारा योगेंद्र प्रसाद को 01 जुलाई 2024 और 01 जुलाई 2025 की वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं रोकी गई। स्कूल के पत्र कर्मांक/स्था/2026/178 दिनांक 27 मई 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के वेतन वितरण से पता चला कि, जुलाई 2025 की वेतनवृद्धि का वित्तीय लाभ भी उन्हें दे दिया गया। विभाग इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मान रहा है। जारी नोटिस में इसे कानूनी आधार पर इस कृत्य को एम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के तहत भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना गया है और ये दण्डनीय अपराध मानते हुए, खण्ड शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र ओझा से मांगा गया जवाब था। विभाग का कहना है कि, दण्डित प्राचार्य की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश का पालन नहीं किया गया, इसलिए बीईओ से जवाब मांगा गया है। विभाग के इस पत्र के बाद हड़कंप है। लेकिन पूरा बॉस पोलता है और इस प्रकरा का ये एक मामला नहीं है अगर विभाग के रिकॉर्ड की जांच की जाए तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं जिसमें विभागीय आदेशों को मनमाने तरीके से बदल दिए गए।

भ्रष्टाचार और प्रशासनिक निठल्लेपन से उपजी पैदल मार्च कर कलेक्टर तक शिकायत पहुंचाने की परम्परा

अब तक विद्यार्थी ही अपनी समस्या लेकर पैदल जिला मुख्यालय तक मार्च कर रहे थे लेकिन अब ग्रामीण भी इसी प्रक्रिया को अपना रहे

माही की गूंज, झाबुआ।

यूं तो हम आजादी के आठवें दशक को पूरा करने जा रहे हैं लेकिन जिले की स्थिति अब भी ढाक के तीन पात ही है। हां इतना जरूर हुआ है कि, जिले में शिक्षा का स्तर भले ही निम्न स्तर पर बढ़ा हो लेकिन जागरूकता के मामले में अब अल्प शिक्षित इस जिले की जनता जागती नजर आ रही है। ग्रामीणों को अपनी समस्याएं समझ आ रही है और वे इस पर दिन ब दिन मुखर होते भी दिखाई दे रहे हैं। ग्राम स्तर की समस्याओं पर बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे हैं और अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जनजागरूकता से उठती इस आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन अपने हक के लिए उठने वाली आवाज जैसे अब दबने वाली दिखाई देती नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ झाबुआ जिले में ही हो रहा है बल्कि पूरे देश में पिछले कुछ महीनों में ऐसे लोग सरकार और प्रशासनिक कारगुजारियों से परेशान होकर अपने हक की लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए हैं। पश्चिमी मध्यप्रदेश का आदिवासी बाहुल जिला झाबुआ भी अब इससे अछूता नहीं दिखाई दे रहा है।

आजादी के बाद से ही आदिवासी बाहुल इस जिले को अशिक्षित होने का तमाग मिलता रहा है, लेकिन आजादी के 8 दशक बाद भी जिले की शिक्षा और शिक्षा प्रणाली में कोई खासा फर्क देखने को नहीं मिला है। अब जिला अशिक्षित तो नहीं है लेकिन अब भी अल्प शिक्षित जिलों की श्रेणी में आता है। गरीबी के मामले में देश में सबसे गरीब श्रेणी वाले जिलों में अब भी झाबुआ और आलीराजपुर प्रथम व द्वितीय स्थान पर है।

पिछले कुछ सालों में अल्पशिक्षित इस जिले में विद्यार्थियों ने अपने शिक्षा के अधिकार को पहचाना है और इसी के चलते जिले के विद्यार्थी पिछले कुछ सालों में कई बार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ खड़े दिखाई दिए हैं। कभी स्कूल में सही भोजन के लिए तो कभी स्कूली पढ़ाई के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए। कभी छात्रावास की अव्यवस्थाओं के लिए तो कभी टीचर्स या प्राचार्य ही हिटलर गिरी के खिलाफ छात्रों को जिले की सड़कें नापते देखा गया है। यह सब कुछ हम उस दौर में देख रहे हैं जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जिला अब भी अल्पशिक्षित होने की श्रेणी में है। इस बात का अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है कि, जब अल्पशिक्षित होने पर जिले में अपने हक और अधिकार की पहचान होने लगी है तो फिर जब जिला बहुशिक्षित होने या शत-प्रतिशत शिक्षित होने की कगार पर पहुंचेगा तो स्थितियां क्या होंगी...?

विद्यार्थियों और छात्रों की शिक्षा और अपने हक की लड़ाई जिले में अब तक देखने को मिलती रही है, लेकिन अब जैसे परिवर्तन की बयार सी आ चुकी है। विद्यार्थियों की तरह ही ग्रामीण भी अपनी मूल भूत समस्याओं और भ्रष्टाचार के विरोध को लेकर कई किलोमीटर का मार्च कर जिले की सड़कें नापने

लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिले में कुछ आंदोलन या प्रदर्शन ऐसे देखने को मिले हैं जो यह बता रहे हैं कि, अब जिलेवासियों में भी जागरूकता आ रही है और वे अपनी मूल भूत सुविधाओं और समस्याओं के लिए अपनी आवाज उठाने लगे हैं। पिछले दिनों जिले की पेटलावद तहसील के ग्रामीण किसान अपनी समस्या को लेकर पैदल 60 किलोमीटर चलकर रोड़ नापते हुए झाबुआ कलेक्टर से मिलने पहुंच गए थे। किसानों की अपनी मांग थी। उन्हें फसल बीमा की राशि नहीं मिल रही थी। ग्रामीण



किसान अपने हक की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयारी कर के झाबुआ जिला मुख्यालय पहुंचे थे। वे लोग अपने साथ करीब 5 दिन का तमाग मिलता रहा है, लेकिन आजादी के 8 दशक बाद भी जिले की शिक्षा और शिक्षा प्रणाली में कोई खासा फर्क देखने को नहीं मिला है। अब जिला अशिक्षित तो नहीं है लेकिन अब भी अल्प शिक्षित जिलों की श्रेणी में आता है। गरीबी के मामले में देश में सबसे गरीब श्रेणी वाले जिलों में अब भी झाबुआ और आलीराजपुर प्रथम व द्वितीय स्थान पर है।

मंगलवार को भी ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय पर देखने को मिला। झाबुआ जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत उमरिया वजंत्री के ग्रामीण अपनी समस्या और भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर पैदल ही जिला मुख्यालय पहुंच गए।

ग्रामीणों का कहना था कि, ग्राम पंचायत में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो काम हुए ही नहीं उसकी भी राशि निकाल कर बंदर बांट कर ली गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि, सरपंच, सचिव और अन्य अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए की शासकीय राशि निकाल ली गई है। जब इस मामले में सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गई। इसी मामले को लेकर मंगलवार को उमरिया वजंत्री के ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि, पंचायत भवन की मरम्मत के काम पर राशि निकाल ली। जबकि भरतल पर कोई कार्य हुआ ही नहीं। आदर्श ग्राम योजना के तहत बना मिडिल स्कूल का सीसी रोड महज 2 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी तरह ग्राम में पुलिया का निर्माण किए बिना ही भुगतान कर दिया गया। वहीं भूरिया फ्लिए में पुलिया निर्माण में केवल सीमेंट के बिल लगाकर कार्य पूर्ण दर्शा दिया गया। सिंगाड फलिये में भी बिल और बैक भुगतान की राशि में भारी

अंतर पाया गया। ग्रामीण बताते हैं कि, गांव के सामुदायिक भवन पर 5 वर्षों से सरपंच पति के भाई का अवैध कब्जा है। ग्रामीणों ने इसे मुक्त कराने की आवाज भी उठाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि, यदि 7 दिनों में जांच शुरू कर कार्रवाई नहीं की गई तो वे कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे।

सवाल यह कि, यह जिले में कोई पहला मामला नहीं है जब किसी पंचायत में इस तरह के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इससे पहले भी जिले की कई ग्राम पंचायतों में इस तरह के मामले देखने को मिले हैं, जिसमें बिना कार्य किए ही भुगतान कर दिया गया और सरकारी राजस्व को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर बंदरबांट कर ली गई। ऐसी पंचायतों के मामले उजागर होने के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया लेकिन बात सिर्फ उगारानी और कुर्की तक ही सिमट कर रह गई। ना कोई निलंबन देखने को मिला और ना ही सेवा समायो की कार्रवाई।

पिछले कुछ महीनों में जिले में ऐसी कई ग्राम पंचायतों में ऐसे मामले सामने आए हैं लेकिन प्रशासनिक ढर्रा है कि आगे बढ़कर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उमरिया वजंत्री के जागरूक ग्रामीणों ने इस मुद्दे को उठाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद है कि उमरिया वजंत्री के ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न अब भी जहां का तहां ही खड़ा है। क्या जिले में यह कुछेक पंचायतें ही हैं जहां गड़बड़ियां हुई हैं...? आखिर क्यों प्रशासन खुद आगे बढ़कर जिले की तमाम पंचायतों का ऑडिट नहीं कर रहा है? जब इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं और ग्रामीण भ्रष्टाचार व समस्याओं को लेकर मुखर हो रहे हैं, तब तो कम से कम जिला प्रशासन को सोचना ही चाहिए। क्योंकि जिन पंचायतों में इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हुए उससे यह अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि जिले की अन्य ग्राम पंचायतों के हाल कैसे होंगे...?

अब जिले के ग्रामीण लगातार अपनी समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर जिला मुख्यालय की ओर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भी यही है कि, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक निठल्लेपन से परेशान ग्रामीण अब उब चुके हैं और इसी से उपजी पैदल मार्च कर कलेक्टर तक शिकायत पहुंचाने की परम्परा अब लगातार आगे बढ़ने लगी है। पहले जिले में सिर्फ विद्यार्थियों को ही इस तरह के आंदोलन या प्रदर्शन करते देखा गया था लेकिन अब जिले के ग्रामीण भी इसी तरह के आंदोलन और प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

सरकार और जिला प्रशासन को बिना देर किए अब अपने ढेर को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि अब जिले का ग्रामीण जाग चुका है। वह अपनी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों को समझने लगा है और उसके लिए आवाज भी उठाने लगा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली के खिलाफ जिलेवासी और ज्यादा मुखर होंगे। तब स्थितियां क्या होंगी कहा नहीं जा सकता...।

गूंज असर: बौखलाया कन्याशाला का संकुल प्राचार्य

प्राचार्य की करतूत ऐसी कि अपना पूरा गुनाह अन्य शिक्षक पर मढ़ उसके हार्ट अटैक का बना कारण

माही की गूंज, खवासा।

शासकीय कन्या हाई स्कैकेडों का प्राचार्य इतना मीठा की लोगों को अपनी मीठी-मीठी बातों से इस तरह मोह लेने की बात करता है कि, उसके जैसे जवाबदार, आदर्शवादी, विवेकशीलता, समझदार व ईमानदार प्राचार्य कोई और हो ही नहीं सकता और यह मीठा ठग ऐसा कि कड़वा-कड़वा धु, और मीठा-मीठा गट कर लेता है।

उक्त प्राचार्य की कई अनियमितताएं सामने आईं और हर बार अपनी मीठी-मीठी व चिकनी-चुपड़ी बात कर अपने आप को राजा हरिश्चंद्र और प्रत्येक सामने वाले को गात उठराने में महारत हासिल है।

उक्त ढोंगी प्राचार्य की एक कास्तानी पिछले वर्ष में यह सामने आई थी कि, छात्राओं के रिजल्ट में त्रुटियां थी जिसमें फेल बच्चों को पास व

ऐसी कई कास्तानी ढोंगी प्राचार्य की रही। इसी संदर्भ में पिछले दिनों माही की गूंज के सामने जनिहित में एक मामला आया था जिसमें कन्या संकुल के अंतर्गत ग्राम पंचायत भेरुगढ़ के ग्राम छोटी रामगढ़ में शासकीय प्राथमिक शाला जर्जर होकर अनुपयोगी है और बच्चों को अन्य निजी मकान में बिठाकर बच्चों को अध्ययन करवाया जा रहा है। तथा पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। जिस संबंध में माही

की गूंज कार्यालय से प्राचार्य से जर्जर भवन की जानकारी ली थी। जिस पर प्राचार्य ने पूरे मामले से अनभिज्ञता बताई, तथा कहा कि किसी भी भवन के संबंध में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ शिक्षकों के वेतन को निकलवाना होता है।

प्राचार्य की कही बात के साथ 30 जुलाई 2026 के अंक में "स्कूल भवन जर्जर बच्चे निजी मकान में अध्यनरत पर संकुल प्राचार्य अनभिज्ञ" शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित हुआ था।

उक्त समाचार प्रकाशित होने

के बाद असर यह हुआ कि, ढोंगी प्राचार्य जमकर बौखलाया और उसकी बौखलाहट जब हमारा पेपर वितरक अगले अंक 6 अगस्त का जब पेपर वितरण करने गया तो पेपर वितरक के समक्ष अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए कहा कि, माही की गूंज अखबार किसका है...? पेपर वितरक ने कहा संजय भट्टेवरा का। जिसके बाद प्राचार्य कहते हैं कि, बिना जानकारी लिए हमारा समाचार छप दिया...? जिस पर बात पेपर वितरक की जानकारी में होकर प्राचार्य को कहां साहब आपकी दी हुई जानकारीनुसार तो पिछले अंक में समाचार प्रकाशित हुआ था। जिस पर साहब अपने स्टॉफ के सामने बोलीतनी नहीं निकली और अपनी बौखलाहट के साथ रोब झाड़ते हुए कहा कि, जाओ,कह देना मैं जो भी गलती करू वह छाप देना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता...!

साहब की यह बौखलाहट पूरी तरह से दर्शाती है कि अपनी मीठी-मीठी बात कह कर लोगों को जो बात कहता है वह निराधार ही होती है। जैसे की प्राचार्य की कही बात जिसमें संकुल क्षेत्र के आने वाले किसी भी संकुल भवन की स्थिति के संबंध में उनकी कोई जवाबदारी नहीं है कहा और उस बात के साथ माही की गूंज ने प्रकाशित किया।

प्रकाशन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तब ही पत्रकार को इस तरीके से बात करने पर मौखिक लताड लगाई होगी। जिसका नतीजा यह रहा है कि उक्त मामले में पूरी जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, प्रकाश भूरिया इसमें स्कूली तरह से अकेला गुनेहवार नहीं था, इसमें ऑपरेटर के साथ मुख्य गुनेहवार यह ढोंगी प्राचार्य ही था।

पूरा मामला प्रकाश भूरिया पर मढ़ने के बाद बताया जा रहा है कि, प्रकाश भूरिया का स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बाद प्रकाश भूरिया की पत्नी भी कन्या शाला स्कूल खवासा पहुंची और ढोंगी प्राचार्य की स्कूल में सार्वजनिक लू उतार दी थी। और कहा था कि, मेरे पति पर पूरा मामला मढ़ कर आपने सही नहीं किया है और आज नहीं तो कल इसकी सजा भगवान देगा।



30/07/2026 को प्रकाशित उक्त समाचार के बाद बौखलाया प्राचार्य।